



दक्षिण भारत राष्ट्रमत



தக்ஷிண பாரத ராஷ்டிரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बंगलूर से एक साथ प्रकाशित

5 तृणमूल से पाई पाई वसूल करेगी भाजपा : शाह

6 जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के आरोपों से हिला कॉर्पोरेट तंत्र

7 सुमोना चक्रवर्ती का फिटनेस मंत्र, 'अनुशासन ही असली जीत है'

फास्ट टैक

श्रीलंका ने 230 से अधिक ईरानी नौसैनिकों को उनके देश भेजा

कोलंबो/भाषा। श्रीलंका में अमेरिकी पनडुब्बी हमले और इंजन फेल होने की घटनाओं के बाद संकट में फंसे ईरानी नौसैनिकों के दो जहाजों के 230 से अधिक नौसैनिकों को स्वदेश भेज दिया गया है। रक्षा अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। कुल 238 नौसैनिकों को मंगलवार देर रात तुर्किये की एक एयरलाइन के विमान से वापस भेजा गया। चार मार्च को ईरान का नौसैनिक जहाज 'आईरिस डेना' श्रीलंका के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के बाहर अमेरिकी हमले का शिकार हुआ था, जिसमें 84 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। इस घटना में 32 अन्य लोगों को श्रीलंका ने बचाया था। इसके तीन दिन बाद ईरान के दूसरे जहाज 'आईरिस बुशहर' को इंजन खराब होने की सूचना के बाद श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

रोहिंग्या समेत 250 लोगों को ले जा रही नौका अंडमान सागर में डूबी

ढाका/एपी। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी और प्रवासन एजेंसियों ने बताया कि हाल ही में अंडमान सागर में मलेेशिया जा रही एक नाव पलटने से कम से कम 250 लोग लापता हो गए हैं, जिनमें रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि विवरण अभी स्पष्ट नहीं हैं लेकिन बांग्लादेश तटरक्षक बल के प्रवक्ता लॉफ्टिनैंट कमांडर सबीर आलम सुजान ने बुधवार को बताया कि नौ अग्रेल को नौ लोगों को बचाया गया, जिनमें तीन रोहिंग्या और छह बांग्लादेशी शामिल हैं। सुजान ने बताया कि बांग्लादेश के ध्वजवाहक पोत एम.टी. मेघना प्राइड ने इन नौ लोगों को तब बचाया, जब जहाज के चालक दल ने नाव पलटने के बाद उन्हें समुद्र में तैरते हुए पाया।

रूस-चीन संबंध मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बहुमूल्य : चिनफिंग

बीजिंग/एपी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बुधवार को कहा कि बदलावों और उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में रूस-चीन संबंधों में मौजूद स्थिरता और निश्चितता खास तौर पर बहुमूल्य है। बीजिंग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के दौरान चिनफिंग ने कहा कि इस तरह की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों की मजबूत जीयंतता और अनुकरणीय महत्व और भी अधिक स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है। सरकारी प्रसारक 'सीसीटीवी' की खबर के मुताबिक, चिनफिंग ने कहा कि चीन और रूस को दोनों देशों के वैध हितों और 'ग्लोबल साउथ' के देशों की एकता की रक्षा करने के लिए अपने गहरे एवं मजबूत रणनीतिक सहयोग का इस्तेमाल करने की जरूरत है।



तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रमुक की हार तय है : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नागरकॉइल (तमिलनाडु) / भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए राजग उम्मीदवारों के समर्थन में बुधवार को एक रोडशो किया और कहा कि अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला

गठबंधन "निश्चित रूप से जीतेगा" जबकि सत्तारूढ़ द्रमुक की हार तय है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कवणम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव एडम्पाडी के. पलानीरवामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और उनके पूर्ववर्ती के. अन्नामलाई के साथ कन्याकुमारी जिले के नागरकॉइल में मोदी एक सजे-धजे याहन के ऊपर खड़े होकर, सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इस कब्र में वेम्पामुडु जंक्शन से वडासेरी तक लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री पर लोगों ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। रोडशो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने "मोदी, मोदी" और "भारत माता की जय" के नारे लगाये।

महिला आरक्षण के नाम पर

ओबीसी का "हिस्सा चोरी" करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिला आरक्षण के नाम पर अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) का "हिस्सा चोरी" कर सकते हैं, जो "राष्ट्र विरोधी गतिविधि" है। राहुल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए जाने से एक दिन पहले जारी वीडियो संदेश में



कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो वह वर्तमान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कर सकती है और परिसीमन भी नई जनगणना के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओबीसी की आबादी का आंकड़ा होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी महिला

आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करती है, लेकिन सरकार इसके नाम पर कुछ और करना चाहती है। उन्होंने दावा किया, "अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना के आधार पर नई जनगणना के आधार पर यह (महिला आरक्षण) निर्णय लिया जाए। प्रधानमंत्री आपकी (ओबीसी) भागीदारी आप से छीन रहे हैं। वह चाहते हैं कि 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्गों की संख्या नहीं है। वह आपकी (ओबीसी) भागीदारी छीनना चाहते हैं।"

ईडी ने 'आप' सांसद अशोक मित्तल से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर छापे मारे

जालंधर/नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की जांच के तहत आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल और उनके तथा उनके परिवार द्वारा पंजाब और हरियाणा में स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जालंधर,

उसके आसपास के इलाकों और गुरुग्राम में लगभग 10 स्थानों पर फेमा के तहत तलाशी ली गई। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि इसमें फगवाड़ा (कपूरथला जिला) स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) का परिसर और गुरुग्राम में स्थित टेटू कॉलेज ऑफ बिजनेस और मार्स्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस नामक दो संबद्ध शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।

व्यापारिक नौवहन पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तथा इसके वैश्विक प्रभावों की पृष्ठभूमि में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को समुद्री नौवहन के "सुरक्षित एवं निबंधित" मार्ग के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमले "पूरी तरह अस्वीकार्य" हैं।

जयसवाल ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के संदर्भ में भारत की राजनयिक चर्चा जारी है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच मंगलवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत का व्यापक संदर्भ साझा किया। जयशंकर ने कल अपने इजराइली समकक्ष गिदोन सार से बात की और पश्चिम एशिया में संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

जयसवाल ने कहा कि जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से भी बात की, और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में संघर्ष पर विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री ने उर्जा बाजारों में आपूर्ति सुखला व्यवधानों पर चर्चा के लिए जापान द्वारा बुलाई गई 'एजेसीएस प्लस' ऑनलाइन बैठक में विदेश मंत्री ने संबंधित टिप्पणी की। बुधवार को पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में,

नाकाबंदी जारी रही तो फारस की खाड़ी बंद कर देंगे : ईरान

काहिरा/एपी। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान के कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता है, तो ईरान फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर में नियत एवं आयात पूरी तरह बंद कर देगा। ईरान की सरकारी मीडिया ने कमांडर अली अब्दुल्लाही के हवाले से कहा, "ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहेगा।" उन्होंने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी युद्धविराम का उल्लंघन है। इजराइल और अमेरिका ने जब ईरान पर हमले शुरू किए थे, तब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। सोमवार को अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह क्षेत्रों में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे जहाजों की नाकाबंदी शुरू कर दी और कहा कि वह फारस की खाड़ी में अन्य जहाजों के आवागमन की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालेगा।

बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने ली शपथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सम्राट चौधरी ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लोपेन्टेन जेनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने लोकभवन के राजेंद्र मंडप में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद चौधरी इस पद पर आसीन होने वाले, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं। राज्य के इतिहास में यह पहली बार है जब भाजपा के किसी नेता ने मुख्यमंत्री पद संभाला है।



सम्राट चौधरी के अलावा जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विजय चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी ने शपथ लेते ही कई अहम राजनीतिक उपलब्धियां अपने नाम दर्ज कीं। वह बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ही वह उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं, जो उपमुख्यमंत्री पद से सीधे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। करीब 59 वर्षों बाद यह उपलब्धि दोहराई गई है। इससे पहले 1967 में उपमुख्यमंत्री बने जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में मुख्यमंत्री पद संभाला था।

नया आयकर कानून आधुनिक, पारदर्शी कर प्रणाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम : राष्ट्रपति



नागपुर/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि आयकर अधिनियम, 2025, जो एक अप्रैल से लागू हुआ है, एक आधुनिक, सरल और पारदर्शी कर प्रणाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वह यहां राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) में भारतीय राज्य सरकारों के 78वें बैठक के

समापन समारोह में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ऐसे समय में प्रशासनिक व्यवस्था और उससे जुड़े हर संस्थान की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि प्राचीन

भारतीय विचारक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में शासन का एक शाश्वत सिद्धांत दिया था कि जिस प्रकार एक मधुमक्खी फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार एक शासक को लोगों पर अनावश्यक बोझ डाले बिना एक एकरा करना चाहिए।

॥ श्री महावीरय नमः ॥
॥ जय आम जय आनंद जय देवेंद्र जय शिव ॥
॥ श्री निहाल खूब फूल सुमति विशाल आशुषि जुक्यो नमः ॥

समकित के संग समकित की यात्रा
बैंगलोर नगर प्रवेश

आगम ज्ञाता, प्रज्ञा महर्षि, बाणी के जादूगर, दक्षिण भारकर, हृदयसम्राट पूज्य गुरुदेव श्री डॉ. समकितमुनिजी म. सा., प्रेरणाकुशल श्री भवोत्तमुनिजी म. सा., गायक कुशल श्री जयवंत मुनिजी म. सा. आदि ढाणा ३ का मंगलमय नगर प्रवेश विलसन गार्डन जैन स्थानक में होगा। इस पावन अवसर पर आप श्री संघ, सपरिवार एवं अपने इष्ट मित्रों सहित पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं एवं हमें सेवा का सुअवसर प्रदान करें।

मंगल प्रवेश
शुक्रवार दिनांक 17.4.2026
प्रातः 7:35 बजे

प्रवेश : तेरापंथ सभा भवन, आडुगुडी, बैंगलूर से रवाना होकर विल्सन गार्डन जैन स्थानक में प्रवेश होगा। कार्यक्रम के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। कृपया विल्सन गार्डन श्री संघ को अतिथि सत्कार का अवसर प्रदान करें।

Bangalore

निवेदक : बैंगलोर चातुर्मास समिति 2026
CHAIRMAN : RAYCHAND CHAJED | PRAKASH BETALA | ASHOK RANKA

15-04-2026 16-04-2026
सूर्योदय 6:21 बजे सूर्यास्त 5:55 बजे

BSE 78,111.24 (+1,263.67)
NSE 24,231.30 (+388.65)

सोना 15,996 रु. (24 कैरट) प्रति ग्राम
चांदी 264,000 रु. प्रति किलो

निशान मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका
epaper.dakshinbharat.com



चुनावी यूटर्न

लो बजा चुनावी बिगुल पुनः फिर से यह मौसम हुआ गर्म। जो बदमिजाज बेहया रहे, उनको भी आने लगी शर्म। जो लिप्त रहे निज कर्मों में, वे याद कर रहे लोक धर्म। हो रहे उज जो सब पर ही, वे सब अब होने लगे नर्म।

माजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड

कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी दोषी करार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। विशेष सांसद-विधायक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हुई हत्या के मामले में दोषी करार दिया। न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने कुलकर्णी के साथ 16 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया, जबकि दो अन्य आरोपियों को बरी कर

दिया गया। अदालत बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगी। भाजपा सदस्य और धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य योगेश गौड़ा की 15 जून 2016 को धारवाड़ स्थित उनके ज़िम में हत्या कर दी गई थी। कुलकर्णी पर इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। घटना के समय यह (कुलकर्णी) राज्य सरकार में मंत्री थे। शुरूआत में स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन 2019 में भाजपा सरकार आने के

बाद इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में 113 गवाहों के बयान दर्ज किए और 2020 में कुलकर्णी को गिरफ्तार किया। विधायक को इस मामले में नौ महीने से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा था जिसके बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली थी। अदालत ने मामले की जांच करने वाली सीबीआई को सभी दोषियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया है।



'दपरे' मुख्यालय में मनाई डॉ. बीआर अंबेडकर जयंती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हवेली। भारत रत्न डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 अप्रैल को दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्यालय 'रेल सोधा' हवेली में डॉ. बी. आर. अंबेडकर जयंती मनाई गई। दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पी. अनंत ने बाबासाहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की और सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने हाशिए पर पड़े समुदायों के उद्धार में और भारत के संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। उन्होंने उल्लेख किया कि डॉ. अंबेडकर-जो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, यकील और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे-ने अत्यंत साधारण और वंचित पृष्ठभूमि से उठकर देश के महानतम नेताओं में से एक बनने का सफर

तय किया। पी. अनंत ने आगे इस बात पर जोर दिया कि अपने कानूनी और बौद्धिक योगदानों से परे, डॉ. अंबेडकर का जीवन इस बात का एक सशक्त प्रमाण है कि कैसे शिक्षा और दृढ़ संकल्प किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को सशक्त बना सकते हैं। समानता, गरिमा और सामाजिक उत्तरदायित्व के उनके शाश्वत आदर्श पीढ़ियों को प्रेरित करते आ रहे हैं, और हमें नागरिकों के रूप में हमारे इस दायित्व के चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की और सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने हाशिए पर पड़े समुदायों के उद्धार में और भारत के संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। उन्होंने उल्लेख किया कि डॉ. अंबेडकर-जो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, यकील और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे-ने अत्यंत साधारण और वंचित पृष्ठभूमि से उठकर देश के महानतम नेताओं में से एक बनने का सफर

शायरी प्रतियोगिता



बेंगलूर के कोरमंगा स्थित सेंट फ्रांसिस महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा गत 13 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर शाम शायराना शायरी प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शायरी प्रेमियों के लिए एक अनुपम अवसर सिद्ध हुआ, जिसमें विभिन्न कॉलेजों से 18 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि एवं निर्णायक मंडल के रूप में डॉ. लता चौहान एवं मिस्टर अकरम उल्ला बेग उपस्थित रहे। महाविद्यालय के निदेशक ब्रदर डॉ. टाइस्ट एंटी एवं प्रधानाचार्य डॉ. आर.एन. सुब्बा राव और विभिन्न विभागों के अध्यापक गण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज बेंगलूर में विकसित करेगी 39 एकड़ की टाउनशिप परियोजना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। रियल्टी कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि वह बेंगलूर में 39 एकड़ की टाउनशिप परियोजना विकसित करेगी, जिसकी अनुमानित राजस्व क्षमता 7,200 करोड़ रुपये की होगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी एक सूचना में कहा कि उसने पूर्वी बेंगलूर के गुंडुरु में 8.63 एकड़ भूखंड के लिए एक संयुक्त विकास समझौते (जेडीए)

पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से कंपनी व्हाइटफील्ड-सरजापुर कॉरिडोर में 39 एकड़ की बड़ी एकिकृत आवासीय टाउनशिप विकसित करने में सक्षम होगी। इसमें कहा गया है, "मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर आवासीय टाउनशिप के रूप में नियोजित 39 एकड़ के विकास का अनुमानित सकल विकास मूल्य (जीडीपी) लगभग 7,200 करोड़ रुपये होगा।" टाउनशिप के लिए भूमि का इंतजाम एकमुश्त खरीद और संयुक्त विकास समझौते के संयोजन के माध्यम से किया जा रहा है।

आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए शाखा विस्तार नियम को सुगम बनाया

मुंबई। भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को परिचालन में लचीलापन प्रदान करते हुए उन्हें अधिकांश मामलों में पूर्व अनुमति के बिना शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। साथ ही जमा स्वीकार करने वाली इकाइयों के लिए शुद्ध स्वामित्व निधि के आधार पर कुछ शर्तें भी लागू कीं। केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - शाखा मंजूरी) संशोधन निर्देश, 2026 जारी किए हैं। एक परिपत्र में कहा गया है कि इन संशोधित निर्देशों का उद्देश्य एनबीएफसी को शाखा विस्तार के लिए परिचालन में लचीलापन प्रदान करना है ताकि कारोबार सुगमता बढ़े और साथ ही आवश्यक नियामक अनुपालन सुनिश्चित हो सके। आरबीआई ने कहा, जब तक विशेष रूप से प्रतिबंधित न हो, एनबीएफसी को आमतौर पर आरबीआई से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना शाखाएं खोलने की अनुमति है। परिपत्र में कहा गया है कि 50 करोड़ रुपये तक की शुद्ध स्वामित्व निधि (एनओएफ) वाली या 'ए' से कम क्रेडिट रेटिंग वाली जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी उस राज्य में शाखा खोल सकती है या एजेंट नियुक्त कर सकती है जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है। यदि ऐसी एनबीएफसी की शुद्ध स्वामित्व निधि 50 करोड़ रुपये से अधिक है और क्रेडिट रेटिंग 'ए' या उससे ऊपर है, तो वह भारत में कहीं भी शाखा खोल सकती है या एजेंट नियुक्त कर सकती है।

एआई जागरूकता पर गिनीज बुक में दर्ज हुआ गोरखपुर का नाम

गोरखपुर (उम्र)/भाषा

कृत्रिम मेधा (एआई) जागरूकता पर गोरखपुर का नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज हुआ है। एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तैयार किए गए 'एआई फॉर ऑल' जागरूकता कार्यक्रम ने एक सप्ताह में 764187 ऑनलाइन पंजीकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। 'महाराणा प्रताप इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' (एमपीआईटी) ने 'टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज' (टीसीएस) और अन्य संस्थानों के

सहयोग से यह कार्यक्रम शुरू किया। बुधवार को 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' के प्रतिनिधि ऋषि नाथ ने योगी आदित्यनाथ और टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण का विश्व कीर्तिमान रचे जाने का प्रमाण पत्र सौंपा। यह प्रमाण पत्र एमपीआईटी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस' के लोकार्पण समारोह के मंच पर सौंपा गया। एमपीआईटी ने 'एआई फॉर ऑल' जागरूकता कार्यक्रम के लिए पांच लाख पंजीकरण का लक्ष्य रखा था। इसके लिए निर्धारित तिथि नौ अप्रैल तक 764187 पंजीकरण

हुए। इसके अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय (गोरखपुर), महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य एयुथ विश्वविद्यालय, एमपी पॉलिटेक्निक, आईटीएम गीडा, बीआईटी गीडा आदि को भी साझा पहल में शामिल किया गया। 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' के प्रतिनिधि ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को कड़े मानकों पर परखने के बाद प्रमाण पत्र सौंपा गया है।

प्रचार



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जब वह बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन इवेंट्स में शामिल होने पहुंचीं।

राधाकृष्णन ने समावेशी विकास के लिए एआई को अपनाने का आह्वान किया

नई दिल्ली/भाषा

उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को व्यापक कल्याण के लिए एक शक्ति के रूप में अपनाने का बुधवार को आह्वान किया और कहा कि यह सरकारों को पहले से कहीं बेहतर सेवा करने के लिए सशक्त बना रही है। राधाकृष्णन ने यहां 'सुशासन के लिए एआई' विषय पर आयोजित पांचवें डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि एआई एक समावेशी, कुशल और विकसित भारत के निर्माण में सहायक है। उन्होंने कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने में अग्रणी है, जो 'सबका साथ, सबका विकास' की परिकल्पना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक

तकनीकी क्रांति नहीं बल्कि एक मानवीय क्रांति है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि अब एआई के माध्यम से संसदीय दस्तावेज कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। उन्होंने समावेशी शासन और भाषाई सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत के राष्ट्रीय एआई-संचालित भाषा मंच 'भाषिनी' पर भी प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई-सहायता प्राप्त टीबी स्क्रीनिंग, एआई-सक्षम पोर्टेबल एक्स-रे उपकरणों और ई-संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन मंचों जैसी योजनाओं के माध्यम से एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कृषि, लघु एवं मध्यम उद्यमों, साइबर सुरक्षा, न्यायपालिका और प्रशासनिक

प्रणालियों में भी इसी तरह के परिवर्तनकारी प्रभाव देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शासन हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसी प्रकार एआई भी अब हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने भारत एआई मिशन और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जैसी प्रमुख सरकारी पहल पर प्रकाश डाला, जिनका उद्देश्य देश के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। राधाकृष्णन ने दिल्ली में हाल में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट' का भी जिक्र किया, जहां एआई के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को व्यापक रूप से सराहा गया। उन्होंने बताया कि वैश्विक उद्योग जागत की हस्तियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत की अपार क्षमता पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया।

क्रॉम तकनीक में कर्नाटक की बड़ी छलांग

देश का पहला 'क्रॉम इकोसिस्टम मैप' जारी, 'क्यू-सिटी' की होगी स्थापना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। विश्व क्रॉम दिवस के अवसर पर कर्नाटक ने तकनीकी क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत का पहला 'क्रॉम इकोसिस्टम मैप' जारी करते हुए राज्य के क्रॉम रोडमैप के पहले चरण की औपचारिक शुरुआत की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एन.एस. बोसराजु ने विज्ञान से हकीकत तक कार्यक्रम के दौरान इस पहल की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी क्रॉम क्षमताओं का व्यापक मैप तैयार किया है। इसे आईआईएससी (भारतीय विज्ञान संस्थान) के सहयोग से विकसित किया गया है।



'डीप टेक दशक' घोषित किया है। सरकार ने क्रॉम कोशल विकास और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ के शुरूआती अनुदान और डीप टेक के लिए 400 करोड़ के विशेष फंड की घोषणा की है। सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रसिद्ध प्रोफेसर अरिंदम घोष को कर्नाटक क्रॉम टास्क फोर्स का चेयरमैन नियुक्त किया है। वे 'क्यू-सिटी' की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और राज्य की भविष्य की तकनीकी रणनीतियों की देखरेख करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों प्रो. अरिंदम घोष, प्रो. अक्षय नायक, नागेंद्र नागराज का सम्मान किया गया। इस अवसर पर इसरो के पूर्व चेयरमैन किरण कुमार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

दावणगेरे उपचुनाव : कांग्रेस ने विधायक जब्बार को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डॉ. के. शिवकुमार ने बुधवार को दावणगेरे दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए विधायक के. अब्दुल जब्बार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शिवकुमार ने रविवार को जब्बार का पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया

और उनके अधीन गठित समितियों को भंग कर दिया। यह कार्रवाई मुस्लिम नेताओं के एक समूह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद की गई जिन्होंने दावणगेरे दक्षिण में आधिकारिक उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी ही पार्टी के सदस्यों पर ध्वजंत्र रचने का आरोप लगाया था। शिवकुमार ने एक विज्ञापन में कहा, दावणगेरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के हालिया उपचुनाव में उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर, विधान परिषद सदस्य अब्दुल जब्बार को विधानसभा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया

जाता है। विधायक जब्बार दावणगेरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट दिवंगत विधायक और पार्टी के दिग्गज नेता शमनूर शिवशंकरप्पा के पोते समर्थ मल्लिकार्जुन को मिल गया। शिवशंकरप्पा के निधन के कारण नौ अप्रैल को उपचुनाव कराया गया। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने सोमवार को विधायक नसीर अहमद को राजनीतिक सचिव के पद से हटा दिया। अहमद पर उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ काम करने का आरोप है।

दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के एक दिन बाद, 10 अप्रैल को कर्नाटक कांग्रेस में दरार पैदा हो गई। मुस्लिम नेताओं के एक समूह ने आरोप लगाया कि कुछ वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने दावणगेरे दक्षिण में आधिकारिक उम्मीदवार को हराने के लिए आंतरिक साजिश रची है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी पहलुओं पर विचार करने और मुस्लिम नेताओं को शिक्षा में लेने के बाद समर्थ मल्लिकार्जुन को उम्मीदवार बनाया था। इसके बावजूद, एक अभियान चलाया गया जिसमें कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को टिकट न देकर धोखा देने का आरोप लगाया गया।

सिद्धरामय्या ने प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंप आरक्षण सहित 18 मुद्दों पर हस्तक्षेप का अनुरोध किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 18 मुद्दों पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य की 56 प्रतिशत आरक्षण नीति को संवैधानिक संरक्षण देने और घाटा अनुदान जारी करने की मांग भी शामिल है। सिद्धरामय्या ने कहा कि राज्य की योजनाओं को मंजूरी और धन जारी करने में देर सरकार की ओर से बार-बार होने वाली देरी से व्यवस्थागत भेदभाव की धारणा पैदा हुई है।

मुख्यमंत्री ने संविधान की नौवीं अनुसूची में कर्नाटक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 56 प्रतिशत आरक्षण संबंधी कानून को शामिल करने और एसटी की केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कुछ जातियों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान, बेंगलूर को विशेष अनुदान जारी करने और मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देने सहित अन्य पर जोर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी बयान के मुताबिक मांड्या जिले के आदिचुंचनगिरि जाने के लिए प्रधानमंत्री शहर के एचएएल हवाई अड्डे पर पहुंचे थे और उसी समय मुख्यमंत्री ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। सिद्धरामय्या ने मोदी को लिखे पत्र में कहा, कर्नाटक ने हमेशा जिम्मेदारी और दूरदर्शिता के साथ भारत के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस किया है। हालांकि, मंजूरी और धन जारी करने में बार-बार होने वाली देरी ने प्रणालीगत असमानता की धारणा पैदा की है। इन

चिंताओं को दूर करने से सबे सहकारी संघवाद की भावना मजबूत होगी और भारत के विकास के लिए हमारी साझा दृष्टि मजबूत होगी। उन्होंने कहा, कर्नाटक के लोग इन मुद्दों के समाधान में आपके हस्तक्षेप की आशा करते हैं। मुझे भरोसा है कि केंद्र सरकार कर्नाटक को भारत के समावेशी और सतत विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी। सिद्धरामय्या ने कहा, हमारा राज्य प्रगतिशील और समावेशी भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है और सहकारी संघवाद के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। उन्होंने कहा, हालांकि कर्नाटक राष्ट्रीय खजाने में सबसे बड़ा योगदान देने वालों में से एक है तथा आर्थिक और सामाजिक विकास में अग्रणी है, कुछ लंबे समय से लंबित मुद्दों पर केंद्र सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने



बुधवार को बेंगलूर के एचएएल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या।

रेखांकित किया कि रेल बजट में घोषित कोलार रेलवे कोच फैक्टरी के लिए राज्य द्वारा 1,123 एकड़ भूमि की पेशकश के बावजूद इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पुनर्जीवित करने से पिछड़े कोलार क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सिद्धरामय्या ने कहा कि प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में बेंगलूर-मैसूरु खंड को शामिल करना संतुलित क्षेत्रीय विकास और संपर्क बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सम्मानपूर्वक केंद्र सरकार से बेंगलूर उपनगरीय रेल परियोजना के लिए प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता जारी करने में तेजी लाने और किटूर कर्नाटक और कल्याण कर्नाटक के प्रमुख जिलों को जोड़ने वाले बेंगलूर-मुंबई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू करने का आग्रह करता है। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत

सुरक्षित पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 17,554 करोड़ रुपये के लंबित केंद्रीय अंश को जारी करने की मांग की। सिद्धरामय्या ने कहा कि ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान जारी करने की सभी शर्तें पूरी करने से बावजूद कर्नाटक को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,860 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए समय पर राशि का आवंटन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे ज्ञापन में लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, राजस्व घाटा के मद में 5495 करोड़ रुपये जारी करने, बेंगलूरु जल संकट के समाधान के लिए मेकेदातु परियोजना और लंबित सिंचाई परियोजनाओं का मुद्दा भी उठाया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में रोडशो किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नागरकोडुल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को कन्याकुमारी जिले में रोडशो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग

शामिल हुए। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेन्द्रन और उनके पूर्ववर्ती के अन्नामलाई के साथ, मोदी एक सजे-धजे वाहन के ऊपर खड़े होकर सड़क के दोनों ओर कतार में बड़ी संख्या में खड़े

लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इस कस्बे में वेप्पामुडु जंक्शन से वडासेरी तक लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री पर लोगों ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा।

परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की आवाज दब जाएगी : चिदंबरम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयंबटूर। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को दावा किया कि इस कदम से दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक आवाज दब जाएगी। उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य भी इससे वंचित हैं। उन्होंने 16 अप्रैल से संसद सत्र आयोजित किए जाने को 'सुनियोजित साजिश' करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार में व्यस्त तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सांसदों को सत्र में भाग लेने से रोकना है। कांग्रेस द्वारा इन दोनों राज्यों में चुनावों का



हवाला देते हुए सत्र स्थगित करने के अनुरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, 'चुनावों के बाद संसद सत्र आयोजित करने में क्या खतरा है?' उन्होंने कहा, चुनावों के दौरान इस समय संसद सत्र आयोजित करने की कोई हड़बडी नहीं है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी कार्यों के कारण कुल 67 सदस्य सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। चिदंबरम ने कहा कि लोकसभा में तमिलनाडु का

वर्तमान प्रतिनिधित्व 39 है और यह बढ़कर 58 हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की आवाज दबाई जाएगी। उन्होंने परिसीमन विधेयक को नाकाम करने और एकमत होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया। चिदंबरम ने 50 प्रतिशत सीटों की वृद्धि और राज्य में परिसीमन के प्रतिकूल प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस नेता ने कहा, 'अन्नाद्रमुक के महासचिव पलानीस्वामी की परिसीमन पर प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है, जिसमें उन्होंने अमित शाह के इस आश्वासन का हवाला दिया है कि इससे तमिलनाडु प्रभावित नहीं होगा।' चिदंबरम ने लोगों से केंद्र द्वारा शुरू की गई परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करने की भी अपील की।



विजय के दो सीट से चुनाव लड़ने के निर्णय ने पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व को 'हाई-प्रोफाइल' बनाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभिनेता-राजनेता विजय द्वारा चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दो सीट से चुनाव लड़ने के विकल्प को चुनने के बाद ये दोनों सीट हाई-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र बन गईं। तमिलनाडु के कर्णम (टीवीके) के प्रमुख विजय, एक ही साथ दो सीट से चुनाव लड़ने वाले पहले नेता नहीं हैं। जयललिता ने 1991 में बरगुर और कांगेयम सीट से चुनाव लड़ा और दोनों सीट पर जीत हासिल की थी।

जिसके बाद वह पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनीं। पृथिव्या तमिलनाडु पार्टी के संस्थापक के. कृष्णासामी ने 2016 के चुनावों में दो आरक्षित सीट ओट्टापिडारम और वालपराई से चुनाव लड़ा तथा वह दोनों में हार गए थे। विजय द्वारा चुने गए दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में काफी संख्या में श्रमिक वर्ग निवास करते हैं और ईसाइयों का एक बड़ा हिस्सा भी मौजूद है। विजय के अपने पहले ही चुनाव में दो सीट से मैदान पर उतरने के फैसले पर द्रविड़ मुनेत्र कणम (द्रमुक) की युवा शाखा के सचिव उदयनिधि स्टालिन ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। उदयनिधि ने हाल ही में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए कहा, उनका एक पैर इधर है, दूसरा उधर, लेकिन हमारे 'विजेता उम्मीदवार' इनिगो इरुवयाराज यहां तिरुचिरापल्ली पूर्वी निर्वाचन

क्षेत्र के स्टार उम्मीदवार हैं। हालांकि इनिगो को दो निर्वाचन क्षेत्रों में ईसाई समुदाय के बीच अच्छा प्रभाव है, लेकिन फिर भी उन्होंने तिरुचिरापल्ली पूर्व से दूसरी बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अपने नेता का बचाव करते हुए टीवीके के महासचिव आधव अर्जुन ने कहा कि विजय एक साहसी और स्वतंत्र नेता हैं, जिन्होंने राज्य में स्थापित राजनीतिक ताकतों को चुनौती दी। अर्जुन ने पूरे तमिलनाडु में 'विजय लहर' का दावा करते हुए कहा कि टीवीके के संस्थापक में 'मानसिक शक्ति' है और वह 'धमकियों' से डरेंगे नहीं। पेरम्बूर सीट पर परंपरागत रूप से द्रमुक, अन्नाद्रमुक, कांग्रेस और माकपा के सदस्य चुने जाते रहे हैं तथा वर्तमान में द्रमुक के आर. डी. शेखर को फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। शेखर ने 2021 में यह सीट जीती थी।

चेन्नई और संतरागाछी के बीच विशेष ट्रेन आज

चेन्नई। दक्षिण रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन संख्या 06067/06068 डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - संतरागाछी - चेन्नई बीच सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। ट्रेन संख्या 06067 डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - संतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल 16 अप्रैल गुरुवार को सुबह 06:55 बजे डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से प्रस्थान करेगी और आगे दिन दोपहर 12:30 बजे संतरागाछी पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 06068 संतरागाछी - चेन्नई बीच सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल 17 अप्रैल, शुक्रवार को दोपहर 2:50 बजे संतरागाछी से प्रस्थान करेगी और आगे दिन शाम 6:30 बजे चेन्नई बीच पहुंचेगी। इस ट्रेन में 1 - एसी टू टियर कोच, 1 - एसी थ्री टियर कोच, 18 - स्लीपर क्लास कोच और 2 - द्वितीय श्रेणी की बसें (दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल) कोच होंगे।

स्टालिन ने तमिलनाडु में काले झंडे लगाकर प्रदर्शन की घोषणा की, कहा-

केंद्र को 'भारी कीमत' चुकानी होगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के खिलाफ 16 अप्रैल को पूरे राज्य में काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन की घोषणा की और केंद्र को चेतावनी दी कि यदि उसने तमिलनाडु की आवाज पर ध्यान नहीं दिया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और 'भारी कीमत' चुकानी पड़ेगी। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कणम (द्रमुक) के अध्यक्ष स्टालिन ने परिसीमन के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी सांसदों और पार्टी जिला सचिवों की एक आपात बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा, 'हमारे सिर पर लटकी तलवार अब हम पर आ गिरी है।' उन्होंने कहा कि द्रमुक सभी राज्यों के सांसदों से संपर्क साध रही है और इस 'गंभीर खतर' का पता चलाने के लिए समन्वित रणनीति तैयार कर रही है। एक बयान में स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बृहत्परिणाम को संसद में लाया जाने वाला परिसीमन संशोधन तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के खिलाफ एक घोर 'ऐतिहासिक अन्याय' है। उन्होंने आरोप लगाया कि



परिसीमन की प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों के खिलाफ है। उन्होंने पूछा कि क्या परिसीमन प्रक्रिया भारत की प्रगति में योगदान देने की सजा है? उन्होंने यह पूछा, 'क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों को इस तरह से इनाम दिया जा रहा है?' उन्होंने दावा किया कि स्वाभाविक रूप से विध्य के दक्षिण क्षेत्र का हर दक्षिण भारतीय गुरसे से उबल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'भाजपा आग से खेल रही है। परिसीमन के खिलाफ कल (16 अप्रैल को) समूचे तमिलनाडु में घरों, सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे लगाए जाएंगे।' उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ने तमिलनाडु की आवाज का सम्मान करने और पीछे हटने से इनकार किया तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए

कहा, 'आपको भारी कीमत चुकानी होगी।' उन्होंने कहा कि यह चेतावनी सिर्फ द्रमुक के अध्यक्ष रूप में नहीं दी गई है बल्कि सबसे बढ़कर एक 'स्वाभिमानी तमिल' के रूप में दी गई है। द्रमुक प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी सभी राज्यों से संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा, 'यह पार्टियों या व्यक्तियों के बारे में नहीं है। यह हमारे लोगों के अधिकारों की रक्षा के बारे में है। मैं देश भर की सभी पार्टियों, सांसदों से हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं।' इससे पहले स्टालिन ने दिन में द्रमुक सांसदों के साथ आपात बैठक की और बाद में पार्टी जिला सचिवों की बैठक बुलाई, जिसमें केंद्र द्वारा प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के कारण राज्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के संबंध में चर्चा की

गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, स्टालिन ने अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच धर्मपुरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह आपात बैठक की। मुख्यमंत्री स्टालिन ने मंगलवार को चेतावनी दी थी कि अगर परिसीमन प्रक्रिया में राज्य के हित को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम उठाया गया या उत्तरी राज्यों की राजनीतिक ताकत में अनुचित वृद्धि की गई, तो तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर आंदोलन होंगे, 'पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन' होंगे जिससे राज्य ठप पड़ सकता है।

स्टालिन ने कहा कि 'देश को एक बार फिर 1950 और 1960 के दशक की द्रमुक देखने को मिल सकती है।' उन्होंने स्पष्ट तौर पर पार्टी के शुरुआती दौर की ओर इशारा किया जिसमें पार्टी ने राज्य के अधिकारों और हिंदी को कथित रूप से थोपे जाने के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया था। द्रमुक की स्थापना 1949 में द्रविड़ विचारधारा के दिग्गज नेता सी एन अन्नादुराई ने की थी। उत्तरी तमिलनाडु में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए स्टालिन ने 14 अप्रैल को आरोप लगाया था कि महिला आरक्षण पर मसौदा विधेयक से पता चलता है कि यह 'एक षड्यंत्र' है जो परिसीमन लागू होने पर तमिलनाडु और उत्तरी राज्यों के बीच अंतर को बढ़ाएगा। परिसीमन के खिलाफ समर्थन जुटाने के अपने प्रयासों के तहत स्टालिन ने पिछले साल यह गैर-भाजपा शासित राज्यों की एक बैठक बुलाई थी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तेलंगाना एवं पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान और ए रवंत रेड्डी तथा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित अन्य लोगों ने इस बैठक में भाग लिया था। तेलंगाना के अपने समकक्ष रवंत रेड्डी द्वारा परिसीमन पर पत्र लिखे जाने के बाद मंगलवार को स्टालिन ने उन्हें संदेश दिया कि, 'हमारी एकता हमारे राज्य के अधिकारों की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक न्यायपूर्ण एवं समान भविष्य सुनिश्चित करने के लिए है। दक्षिण एकजुट होकर खड़ा रहेगा, एक स्वर में बोलेंगे और संघवाद की सच्ची भावना को कायम रखेंगे।' रेड्डी ने दक्षिणी राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर एक 'हाइड्रिड मॉडल' का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत प्रस्तावित अतिरिक्त सीट में से 50 प्रतिशत सीट आनुपातिक आधार पर आवंटित की जाएगी और शेष सीट जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) और अन्य मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी।

श्रीलंका के जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में चार भारतीय मछुआरे गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/कोलंबो। श्रीलंका की नौसेना ने बुधवार को बताया कि श्रीलंका के जलक्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में चार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी नाव को ज्वल कर लिया गया है। श्रीलंका के उत्तर मध्य नौसैन्य कमान ने एक बयान में कहा कि उसने सोमवार को श्रीलंकाई जलक्षेत्र में भारतीय नौकाओं के एक समूह को देखा और उन्हें खदेड़ने के लिए कर्मियों को तैनात किया। बयान में कहा गया, नौसेना के कर्मियों ने मछली पकड़ने वाली

भारतीय नौकाओं को ज्वल कर लिया और चार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। नौसेना के अनुसार, इस वर्ष अब तक श्रीलंका के जलक्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में 18 नौकाओं को पकड़ा गया है और 128 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले 11 अप्रैल को कम से कम 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नौकाएं ज्वल कर गई थीं। दोनों देशों के मछुआरे अनजाने में एक-दूसरे के जलक्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है।

उच्च न्यायालय ने उदयनिधि के चुनावी हलफनामे में 'विसंगतियों' से संबंधित मामले में आयकर रिपोर्ट मांगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग से तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा चेन्नई के चेपांक-थिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र से पुनः चुनाव लड़ने के लिए दायर किये गये चुनावी हलफनामों में कथित विसंगतियों पर बुधवार को एक रिपोर्ट मांगी। न्यायमूर्ति एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने चेन्नई के आर कुमारवेल की याचिका पर

सुनवाई करते हुए आयकर महानिदेशक (जांच) और कॉम्पॉर्ट मामलों के मंत्रालय से स्थिति रिपोर्ट मांगी। कुमारवेल ने याचिका में उदयनिधि द्वारा उम्मीदवार के रूप में अपने चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्तियों की जांच का अनुरोध किया था। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल तय की।

चे पांक - थिरुवल्लिकेनी निर्वाचन क्षेत्र के याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2026 में उपमुख्यमंत्री द्वारा दाखिल नामांकन पत्र के साथ संलग्न हलफनामे में उल्लेखित संपत्ति विवरण और 2021 के चुनावों के लिए दाखिल हलफनामे में उल्लेखित संपत्ति विवरण में विसंगतियां थीं। कुमारवेल ने दावा किया कि तुलनात्मक विश्लेषण से सात करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के 'गायब होने' होने का पता चला है और उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग और निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को उदयनिधि द्वारा किए गए वित्तीय खुलासे, आय के स्रोत, लेनदेन और वैधानिक दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा।

तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हमें 'दिल्ली टीम' को बिल्कुल खदेड़ देना है : उदयनिधि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ओट्टापिडारम/कोविलपट्टी। उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर बुधवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव तमिलनाडु और दिल्ली के बीच की लड़ाई है और इस दक्षिणी राज्य को दिल्ली को हराना ही होगा। उदयनिधि ने कहा, 'जैसा कि हमारे नेता (एम के स्टालिन) बार-बार कहते हैं, यह विधानसभा चुनाव दिल्ली बनाम तमिलनाडु का है। हमें तमिलनाडु की टीम बनकर जीतना होगा। हमें दिल्ली की टीम को बिल्कुल खदेड़ना होगा।' थूथुकुडी जिले के ओट्टापिडारम निर्वाचन क्षेत्र में 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव के सिलसिले में एक सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने मतदाताओं से राज्य के



आल्पसम्मान की रक्षा के लिए भाजपा और उसके सहयोगियों को खारिज करने की अपील की। द्रमुक प्रत्याशी एम सी रामजयम के पक्ष में प्रचार करते हुए, उदयनिधि ने उम्मीदवार की सुलभता का जिक्र किया एवं कहा कि रामजयम हमेशा जनता के बीच रहे हैं और जल कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचे जैसे निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देते हैं। उन्होंने द्रमुक सरकार की तुलना पिछली अन्नाद्रमुक सरकार से की, और विशेष रूप से



तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी की स्टारलाइट विरोध प्रदर्शनों और स्कूली बच्चों के लिए हिरासत में हुई मौतों से निपटने के तरीके की आलोचना की। उपमुख्यमंत्री ने द्रविड़ मॉडल सरकार की उपलब्धियों पर जोर देते



हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना और स्कूली बच्चों के लिए सुबह के नाश्ते के कार्यक्रम सहित कई वादे पूरे किए हैं। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने उस पर शिक्षा निधि रोकने और

तमिलनाडु में हिंदी लाने के लिए तीन-भाषा फार्मूला थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होंगे और परिणाम चार मई को घोषित किए जाएंगे।



चुनाव प्रचार

तमिलनाडु मराठा संगम की ओर से तंजापुर के कीलावेली में विठोबा मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कर्नाटक भाजपा मीडिया के अध्यक्ष करुणाराम कासले और कर्नाटक अन्य भाषा समाचार पत्र के अध्यक्ष चंद्रकान्त ने भाग लिया। इसमें तंजापुर के 50 से अधिक मराठा परिवारों ने भाग लिया। उन्होंने तंजापुर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थिरु कर्पू मुरगनंदम का समर्थन किया और उन्हें जीत दिलाने में मदद करने के लिए तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में, तमिलनाडु मराठा संगम के राज्य अध्यक्ष विश्वजीत कडवारे साहेब, तंजापुर जिला अध्यक्ष अलेक्जेंडर भोंसले, तंजापुर जिला सचिव ए. रघुपति राव सूर्यवंशी, तमिलनाडु मराठा संघ के राज्य युवा विंग के सचिव एम. विनोद राव मोहिते और अन्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।



महिला सुरक्षा के लिए हमारी सरकार सजग : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है, इससे महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढ़ेगी। इस अधिनियम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा एवं शिक्षा, सुरक्षा, नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महिलाएं और अधिक योगदान निभा सकेंगी।

शर्मा बुधवार को बिडला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि हमारा समाज और देश तभी प्रगति करेगा, जब महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदारी निभाएंगी। हमारी समाज संस्कृति में महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। हमारी संस्कृति में हर क्षेत्र में महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये आधी आबादी घर को संभालने के साथ ही देश-प्रदेश के विकास में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज महिलाएं स्टार्टअप, शिक्षा, खेल, पुलिस से

लेकर विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 के बाद महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए जन धन योजना, नमो स्त्री योजना और लखपति दीदी जैसी कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर नारी शक्ति को राष्ट्र की प्रगति का आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बालिका लिंगानुपात बढ़ा है तथा स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से घर-घर शौचालय बनाकर माता-बहनों को सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान आवंटित किए जाते हैं। वहीं, प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करवाकर महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की गई है।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में 20 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई। साथ ही, लाडो प्रोत्साहन योजना से अब तक 6 लाख 50

हजार से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया है। मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक 4 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तथा 65 एंटी रोमियो स्कॉड का गठन किया गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में महिला अपराधों के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत अब तक एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी है। महिला दिवस और रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा के साथ गार्गी पुरस्कार, सार्दिकल वितरण, स्कूटी वितरण जैसी योजनाओं से बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने में मदद दी जा रही है।

शर्मा ने कहा कि युवाओं के लिए हमारी सरकार युवा नीति लाई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। हमारी मंशा है कि युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बनें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र में 4 लाख एवं निजी

क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार से ज्यादा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख 25 हजार नई सरकारी नौकरियों की भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। साथ ही, राईजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर सृजित किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में नारी शक्ति केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस अधिनियम से आजादी के बाद पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने का रास्ता है। आने वाले समय में यह अधिनियम देश में बड़ी सामाजिक क्रांति बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से नीतियों में महिलाओं के दृष्टिकोण को प्राथमिकता मिलेगी तथा माता-बहनों देश की हर योजना एवं हर निर्णय में शामिल होंगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सिन्धेवर वाल पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री के साथ छात्रों ने सेल्फी प्यांइट पर सेल्फी ली। इस अवसर पर महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बाघमार, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, महिला एवं बाल विकास शासन सचिव श्रीमती पुनम सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं छात्राएं मौजूद रही।

दक्षिण राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान दें मोदी : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वह दक्षिणी राज्यों द्वारा उठाई गई परिसीमन की चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान दें, अन्यथा यह मुद्दा संवेदनशील रूप ले सकता है। गहलोत ने जयपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि दक्षिणी राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं बढ़ती बेचैनी को दर्शाती हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, दक्षिणी राज्यों के नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए गुस्से और आशंकाओं को प्रधानमंत्री को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं यह जानबूझकर दोहरा रहा हूँ कि यदि दक्षिण के लोग यह महसूस करने लगे कि उत्तर के लोग उनकी स्थिति कमजोर कर रहे हैं, तो हालात बिगड़ सकते हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि यह

मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, उन्होंने 1950 और 60 के दशक के आंदोलनों जैसी स्थिति का संकेत दिया है। यह बहुत खतरनाक संकेत है और वहां की भावना की गहराई को दिखाता है। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। गहलोत ने कहा, सत्ता और विपक्ष दोनों ही महिला आरक्षण चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से परिसीमन को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर सवाल उठते हैं। 2021 में जनगणना क्यों नहीं कराई गई? अब अधिकारी कहते हैं कि इसे एक साल में पूरा किया जा सकता है। गहलोत ने संसद की कार्यवाही के समय पर भी सवाल उठाए और सरकार पर जल्दबाजी का आरोप

लगाया। उन्होंने कहा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, फिर भी संसद बुलाई गई। विपक्षी नेताओं ने चुनाव खत्म होने तक इंतजार करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार जल्दबाजी कर रही है। इससे उनकी नीयत पर संदेह होता है। उन्होंने 2011 की जनगणना को आधार बनाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा, पहले कहा गया था कि नई जनगणना के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। अब अक्टूबर 2011 की जनगणना का हवाला दिया जा रहा है। यह असंगति उचित नहीं है। गहलोत ने कहा कि केंद्र की रणनीति विपक्षी दलों को कठिन स्थिति में डालने की हो सकती है। उन्होंने कहा, यदि विधेयक पारित नहीं होता है तो दोष विपक्ष पर डाला जा सकता है। ऐसी रणनीति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद की विशेष बैठक बुलायी है, जिसमें महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन संबंधी मौजूदा कानून को बदलने वाले विधेयक पेश किए जाएंगे।



राज्यपाल ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के विचार आलोक में राज्यों के निवासियों से किया संवाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। लोकभवन में बुधवार को हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस दौरान इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनसे संवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन में राज्यों के स्थापना दिवस 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को अनुभूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत के राज्य विविधता में एकता की अनूठी

संस्कृति लिए हैं। उन्होंने हिमाचल को भारत का भाल बताते हुए कहा कि हिमाचल तीर्थ भूमि है और राजनीतिक रूप से भी यह राज्य आरंभ से समृद्ध रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार प्राचीन भारत की संस्कृति से जुड़ा है। यहीं से सम्राट अशोक ने विश्वभर में शांति का संदेश पहुंचाया। यहीं भगवान महावीर का जन्म हुआ, गुरु गोविन्द सिंह का जन्म हुआ और यह राज्य पाटलीपुत्र के रूप में समृद्ध भारत का सदा से प्रतिनिधित्व करता रहा है। उन्होंने ओडिशा, अरुणाचल, मिजोरम, दादर एवं नगर हवेली और दमन-दीव से जुड़े इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि भारत राज्यों की विशेषताओं से ही विश्व की समृद्ध संस्कृति का राष्ट्र बना है।

राज्यपाल ने स्थापना दिवस पर विभिन्न राज्यों के लोगों से संवाद करते हुए उन्हें राजस्थान के विकास में भी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने स्थापना दिवस से संबंधित राज्यों की समृद्ध संस्कृति, वीरता और ऐतिहासिक धरोहर को नमन करते हुए 'विकसित भारत' में सभी की समान भूमिका का भी आह्वान किया। इससे पहले विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां के लोगों ने अपने राज्यों की विशेषताओं और राजस्थान से उनके संबंधों के बारे में विस्तार से बताया। राज्यपाल ने व्यक्तिगत रूप से संवाद करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी भी उपस्थित रहे।



अभियंता परियोजना क्षेत्रों में करेंगे नियमित दौरे, फोटो सहित वास्तविक स्थिति की मेजनी होगी रिपोर्ट : रावत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग प्रदेश में जल प्रबंधन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल परियोजनाओं की बजट घोषणाओं और प्रगतिरत कार्यों को समयबद्ध धरातल पर उतार कर अंतिम छोर तक जल उपलब्धता के लिए मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को इंदिरा गांधी नहर भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए जल प्रबंधन परियोजना के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं को गति देने के लिए जयपुर मुख्यालय पर जोनवार अभियंताओं के कैम्प लगाकर कार्य प्रस्तावों को अंतिम

रूप दिया जाए। कैम्पों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने, विभिन्न अनुमतियों के मिलने में देरी और धरातल पर आ रही समस्याओं का समाधान भी निकालें।

रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा जल प्रबंधन को लेकर नियमित समीक्षा की जा रही है। इसलिए परियोजनाओं को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से प्रगतिरत करने का निर्देश दिया। रावत ने कहा कि अभियंता कार्ययोजना बनाकर अपने क्षेत्रों में प्रगतिरत सभी परियोजना क्षेत्रों का नियमित दौरा करें।

कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन से संवाद किया जाए। रावत ने दौरे के फोटोग्राफ और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट हर माह मुख्यालय भेजने

के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में अनावश्यक देरी की जिम्मेदारी सम्बंधित अभियंताओं की तय की जाएगी।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता के लिए पाइप, सरिये, सीमेंट सहित अन्य सामग्री की नियमित जांच करें। उन्होंने परियोजनाओं के कार्यों में देरी के कारणों की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग कराने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा परियोजना क्षेत्र दौरे को लेकर एक विशेष ड्राइव चलाई जा रही है। इसमें अभियंता मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रावत ने सराहना करते हुए ड्राइव को नियमित कराने के निर्देश दिए।

बैठक में देवास, बागोलिया फीडर, अपर हाई लेवल कैनाल, खारी फीडर, पीपलखूट हाई

लेवल, गराडिया एनीकट, थापरा एनीकट, खमेरा लघु सिंचाई, सेई बांध के अधिशेष पानी को जवाई बांध पहुंचाने के लिए सुरंग की क्षमता बढ़ाने, तहसील बारां में पार्वती नहर प्रणाली की पार्वती मुख्य नहर के सुदृढीकरण, हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण कार्य, तकली मध्यम सिंचाई परियोजना में नहर निर्माण, परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई, गागरिन मध्यम सिंचाई, कालीतर लिफ्ट स्क्रीम, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल, ईसरदा, दोहरी लघु सिंचाई सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव भुवन भारकर, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम) अमरजीत सिंह सहित विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

सेवानिवृत्त आईएस सुबोध अग्रवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

जयपुर। जल जीवन मिशन से जुड़े 960 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे पुलिस हिरासत में थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को हिरासत की अवधि पूरी होने पर अग्रवाल को एसीबी अदालत में पेश किया। एसीबी ने अदालत से अग्रवाल की पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन अग्रवाल के वकील ने आपत्ति जतायी और कहा कि अग्रवाल पहले ही एसीबी के सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं।

अदालत ने एसीबी की मांग खारिज करके अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुबोध अग्रवाल के वकील देवांत शर्मा ने कहा कि अग्रवाल ने एसीबी के साथ सहयोग किया है और सभी सवालों के जवाब दिए हैं, इसलिए आगे पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं थी। वकील ने पत्रकारों से कहा कि अग्रवाल के कार्यकाल में केवल चार टेंडर आए थे।



व्यूआर फीडबैक और जीआईएस मैपिंग से आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करें : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर संचालित मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने विभागों एवं जिला कलेक्टरों को सभी गतिविधियों को समयबद्ध रूप से निदेश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों के लिए डायनामिक मास्टर प्लान तैयार कर 15 मई तक पोर्टल पर अपलोड किए जाएं तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से हर स्तर पर जवाबदेही और आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्राम सभा एवं वार्ड सभा के माध्यम से सुझाव संकलन, डेटा एंट्री, ऋद्ध मैपिंग और मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही, 20 अप्रैल तक फोकस ग्रुप डिस्कशन, 25 अप्रैल तक ड्राफ्ट मास्टर प्लान तथा 15 मई तक अंतिम मास्टर प्लान तैयार कर पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठो कोड आधारित फीडबैक प्रणाली विकसित करने तथा नवगठित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों की आईडी मैपिंग शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि अभियान का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो सके।

डेटा एंट्री, मॉनिटरिंग, ऋद्ध आधारित मैपिंग तथा मास्टर प्लान अपलोड की सुविधा उपलब्ध है, जबकि मोबाइल एवं जियो-टैग फोटो अपलोड की व्यवस्था भी की गई है।

वलीनमैक्स, संगम इंडिया ने राजस्थान में हाइड्रिड नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए साझेदारी की

नयी दिल्ली/जयपुर। वलीन मैक्स एनर्जायरो एनर्जी सोल्यूशंस ने राजस्थान में अपने संचालन को कार्बन मुक्त करने के लिए संगम इंडिया के साथ साझेदारी की बुधवार को घोषणा की। शेयर बाजार को दी सूचना के अनुसार, संगम समूह की प्रमुख टेक्स्टाइल इकाई संगम इंडिया का मुख्यालय राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। इस सहयोग के तहत राजस्थान में संगम की पांच इकाइयों को 30 मेगावाट सौर और 20 मेगावाट पवन ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक हाइड्रिड नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे दो मेगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से सुदृढ़ किया जाएगा।

अधिकारियों ने बाल विवाह से दो लड़कियों को बचाया; किशोरी ने रुकवाई अपनी शादी

कोटा। बूंदी जिला प्रशासन ने बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग लड़कियों को बचाया। दोनों लड़कियों का 20 अप्रैल को विवाह होना था। एक नाबालिग लड़के के माता-पिता को भी तब तक उसका विवाह करने से रोक दिया गया, जब तक कि वह शादी की कानूनी उम्र पूरी नहीं कर लेता। अक्षय तृतीया के दौरान बड़ी संख्या में बाल विवाह की आशंका के मद्देनजर बूंदी जिला प्रशासन बेहद सतर्क है और उसने निगरानी बढ़ा

रखी है। माना जाता है कि इस दिन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गुर्जर, रावत, मीणा, बैरवा और कहर समुदायों में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह की योजना की गोपनीय सूचना मिलने पर तहसीलदार नरोत्तम, रायथल थाना प्रभारी हरलाल और 'चाइल्डलाइन' के एक संयुक्त दल ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और दोनों स्थानों पर वैवाहिक कार्यक्रमों को रुकवा दिया। जांच में पता चला कि लड़कियों की उम्र 17 और 15 वर्ष है और वे क्रमशः कक्षा

12 और 10 की छात्राएँ हैं। दोनों लड़कियों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें आगामी कानूनी निर्देशों तक आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया। सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष सीमा मोदार ने बताया कि

इस संबंध में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने दोनों लड़कियों के माता-पिता को उनकी वैधानिक आयु पूरी होने तक विवाह कराने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की कार्यवाही शुरू कर दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में बूंदी सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा ने अपनी शादी खुद रुकवाकर साहस का परिचय दिया। छात्रा ने मंगलवार सुबह सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष से संपर्क कर हस्तक्षेप की मांग की थी। उसने बताया कि वह अपनी पढाई जारी रखना चाहती है, जबकि उसके माता-पिता ने एक मई को खानखेड़ा गांव में होने वाले एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में उसकी शादी तय कर दी है। सूचना मिलते ही चाइल्डलाइन और स्थानीय पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और उसे वहां से निकाला। पोद्दार ने बताया कि परिजनों के कड़े विरोध के बावजूद उनका दल नाबालिग को सुरक्षित ले जाने में सफल रहा। परामर्श के बाद नाबालिग को आश्रय गृह भेज दिया गया।



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

उत्तर प्रदेश में टाटा समूह की उपस्थिति होगी दोगुनी : चंद्रशेखरन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे संभावनाशील औद्योगिक राज्यों में एक है और आने वाले वर्षों में यहां टाटा समूह की उपस्थिति दोगुनी से अधिक होने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल, बेहतर बुनियादी ढांचा और मजबूत नेतृत्व के कारण उद्योगों के विस्तार के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। चंद्रशेखरन ने राजधानी में टाटा मोटर्स की 10 लाखवीं बस के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही।

एक बयान के मुताबिक,



चंद्रशेखरन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा, मजबूत नीतिगत समर्थन और निवेश के अनुकूल वातावरण इसे औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की गति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। राज्य सरकार की नीतियों और सहयोग के कारण उद्योगों को विस्तार का

बेहतर अवसर मिल रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूद अपार संभावनाएं, बढ़ती आर्थिक गतिविधियां और युवा कार्यबल इसे देश की वृद्धि का प्रमुख इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश न केवल औद्योगिक, बल्कि तकनीकी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित टाटा संस केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि आपूर्तिकर्ताओं, भागीदारों और स्थानीय समुदायों के साथ विकसित एक सशक्त पारिस्थितिकी है, जो टाटा समूह और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विश्वास और साझेदारी का प्रतीक है।



तृणमूल से पाई पाई वसूल करेगी भाजपा : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संकल्प जताया कि भाजपा, तृणमूल कांग्रेस द्वारा 'भ्रष्टाचार के माध्यम से बंगाल की जनता से लूटी गई एक-एक पाई वसूल करेगी।' उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दो दशकों तक सत्ता में रहने के बाद भी भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है।

उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सत्ता से जाना 'निश्चित' है, लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने का काम राज्य के उत्तरी क्षेत्रों से शुरू होगा।

शाह ने कहा, 'मोदी ने गुजरात पर 12 साल शासन किया और केंद्र में भी पिछले 12 साल से नेतृत्व कर रहे हैं; फिर भी उनके खिलाफ एक पैसै तक का किसी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा।' शाह ने रैली में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, 'बंगाल में भाजपा को सत्ता में लाएं और तृणमूल नेताओं द्वारा लोगों से लूटे गए एक-एक पैसै को ब्याज समेत वसूल जाएगा।'

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आने के बाद तृणमूल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने 'शिक्षक भर्ती घोटाले में 300 करोड़ रुपए हड़पे' और उत्तर बंगाल के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत बाढ़ राहत कोष से '100 करोड़ रुपए चुराए।'



'मोदी-नीतीश मॉडल' पर ही चलेगा बिहार : सम्राट चौधरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि राज्य का शासन 'मोदी-नीतीश मॉडल' पर ही आगे भी चलता रहेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इससे एक दिन पहले लंबे समय तक इंतजार पर रहे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। चौधरी ने कहा, 'मैं तुरंत राज्य

की समृद्धि के लिए काम शुरू करूंगा। यह स्पष्ट रहना चाहिए कि बिहार 'मोदी-नीतीश मॉडल' पर ही शासित होता रहेगा। बुधवार को बिहार के पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी को बधाइयों का तांता लग गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं ने विश्वास जताया कि राज्य तेजी से प्रगति करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने में मदद मिलेगी। नीतीश कुमार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया और विकास किया, जिसे नए मुख्यमंत्री आगे बढ़ाएंगे।

नीतीश कुमार ने 'एक्स' पर चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास करेगा और देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी चौधरी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी बिहार के विकास के लिए कार्य करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने में मदद मिलेगी। नीतीश कुमार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया और विकास किया, जिसे नए मुख्यमंत्री आगे बढ़ाएंगे।

केजरीवाल ने ईडी की छापेमारी पर कहा

पंजाब में आगामी चुनाव के लिए अपनी 'तैयारियां' शुरू कर दी हैं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अशोक कुमार मित्तल के खिलाफ छापेमारी किए जाने के बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पंजाब में आगामी चुनाव के लिए 'तैयारियां' शुरू कर दी हैं।

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, जालंधर और गुरुग्राम में करीब 10 स्थानों पर फेमा के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) और गुरुग्राम में स्थित इससे जुड़े दो शैक्षणिक संस्थान ट्रेड कॉलेज ऑफ बिजनेस और मार्सेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस के परिसर भी शामिल हैं। मित्तल को हाल ही में 'आप' का राज्यसभा में उपनेता नियुक्त किया गया है, जहां उन्होंने सांसद राघव चड्ढा की जगह ली है। 61 वर्षीय मित्तल फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी हैं। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

बहरहाल, भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी छापेमारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी 'तैयारियां' शुरू कर दी हैं, जहां फिलहाल 'आप' की सरकार है।

बहन को दो बोरा गेहूं देने से नाराज युवक ने की पिता की हत्या

बलिया (उप्र)/भाषा। बलिया

जिले के रसड़ा क्षेत्र में अपनी बहन को दो बोरा गेहूं देने से नाराज एक व्यक्ति ने अपने पिता की लाठी से प्रहार करके कथित तौर पर हत्या कर दी और मां को जखमी कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक आलोक गुप्ता ने बताया कि रसड़ा थाना क्षेत्र के नरथपुर गांव में बुधवार को 75 वर्षीय महेंद्र चौहान का शव पाया गया था और पास से ही चौहान की पत्नी शैला देवी (68) घायल अवस्था में मिली थी। रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक आलोक गुप्ता ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा शैला देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुप्ता के मुताबिक, महेंद्र चौहान ने अपनी बेटी को दो बोरा गेहूं दे दिया था, जिसका चौहान के बेटे पप्पू ने विरोध किया था। उन्होंने बताया कि दो दिन से चल रहे विवाद के दौरान मंगलवार को पप्पू ने अपने माताह्निता पर लाठी से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस वारदात में चौहान की मृत्यु हो गई तथा शैला देवी गम्भीर रूप से घायल हो गई। गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

स्मृति ईशानी ने बंगाल में 'मातृ शक्ति भरोसा कार्ड' की शुरुआत की

तृणमूल सरकार को आड़े हाथ लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता स्मृति ईशानी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, वित्तीय संकथन करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा राज्य की सत्ता में आती है तो प्रत्येक महिला को 3,000 रुपए की मासिक नकद सहायता दी जाएगी।

स्मृति ने 'मातृ शक्ति भरोसा कार्ड' की शुरुआत करने के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि



पर्याप्त केंद्रीय सहायता के बावजूद, राज्य अब भी 'कट मनी की संस्कृति' से ग्रस्त है। 'मातृ शक्ति भरोसा कार्ड' पश्चिम बंगाल में भाजपा की एक पहल है जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए की प्रत्यक्ष नगद सहायता प्रदान की जाएगी।

यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के रूप में तैयार की गई है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। यदि पार्टी राज्य चुनाव जीतती है, तो इस मासिक सहायता के लिए लाभार्थियों का नामांकन करने हेतु इन कार्डों का उपयोग किया जाएगा।

गुरुग्राम की झुगगी बस्ती में भीषण आग लगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुरुग्राम/भाषा। हरियाणा के गुरुग्राम में बुधवार तड़के सेक्टर 37डी की झुगगी-झोपड़ियों में भीषण आग लग गई, जिससे एलपीजी सिलेंडर फट गए और दहशत फैल गई। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशकत करनी पड़ी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, संभवतः कूड़े के ढेर के पास शॉर्ट

सर्किट के कारण आग सबसे पहले एक खाली भूखण्ड में लगी और तेज हवाओं के कारण यह तेजी से आसपास की झुगगीयों में फैल गई। दूर से ही घना धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। दमकल कर्मियों, पुलिस और नागरिक सुरक्षा टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई घंटों की मशकत के बाद आग पर काबू पाया। इस इलाके में पहले भी इसी तरह की घटना हो चुकी है और निवासियों का कहना है कि वे खाली भूखण्डों में कचरा जमा होने से रोकने के लिए नियमित सफाई की मांग कर रहे हैं।

भारत के लिए सारे प्रारूप में खेलना वरदान है, चुनौती नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत के हरफनमौला वॉशिंगटन सुंदर का मानना है कि क्रिकेट का कैलेंडर अति व्यस्त होने के कारण हर प्रारूप में खेलने वाले खिलाड़ी अब बिरतते होते हैं लेकिन इस जमात को हिस्सा बनना खूबसूरत वरदान है, बड़ी चुनौती नहीं।

भारत के लिए 2017 में पहली बार खेलने वाले सुंदर को कैरियर में कई बार चोटों का सामना करना पड़ा है। यह हालांकि पिछले 18 महीने से भारतीय टीम के नियमित सदस्य हैं। उन्होंने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, 'भारतीय क्रिकेट के लिए हर प्रारूप खेलना बड़ा वरदान है। हम सभी को पता है कि भारतीय टीम हमेशा किस तरह का क्रिकेट खेलती है।' उन्होंने कहा

विभिन्न प्रारूपों में नियमित मौके मिलते रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं दिखती। फिटनेस की बड़ी भूमिका है और आपको समझना होगा कि अलग अलग हालात में शरीर कैसे काम करता है।' सीनियर ऑफ स्पिनर आर अश्विन के संन्यास के बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अधिक मौके मिलने लगे लेकिन छोटे प्रारूप में उन्हें बल्लेबाजी को निखारना पड़ा है।

वह 'पागल' हैं राहुल गांधी : हिमंत

भुवनेश्वर/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को 'पागल व्यक्ति' करार दिया। उन्होंने यह टिप्पणी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा उन पर 'अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने' के आरोपों के जवाब में की। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए यहां हवाई अड्डे पर आए शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह अपने पासपोर्ट का विवरण सार्वजनिक करें और बताएं कि उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की है। राहुल गांधी द्वारा शर्मा को 'देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति' करार देने और पवन खेड़ा के समर्थन में पार्टी के खड़े होने का बयान दिए जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री की यह तीखी प्रतिक्रिया आई है।

ममता सरकार की वजह से बंगाल के लोग केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कालना/भाषा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत सरकार ने राज्य में उनके कार्यान्वयन की अनुमति देने में आनाकानी की है। सीतारमण ने कहा कि बंगाल के लोगों को जिन केंद्रीय योजनाओं

के लाभ से वंचित किया जा रहा है, उनमें आयुष्मान भारत, पीएम किसान और आवास योजना शामिल हैं। उन्होंने दावा किया, तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में आतंक का माहौल बना दिया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। आपके हिस्से की राशि दिल्ली में तैयार थी, लेकिन तृणमूल सरकार ने इसे राज्य में खर्च करने की अनुमति नहीं दी।

सीतारमण ने ममता सरकार पर बंगाल में कई योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में केवल सत्ताधारी पार्टी



के 'सिंडिकेट' का हिस्सा होने से ही लाभ सुनिश्चित हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा, बंगाल के गरीब लोगों को पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जिसके तहत केंद्र की ओर से मुफ्त राशन दिया जाता है। राज्य के मंत्री इसके लिए आवंटित धनराशि हड़प

रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में स्कूल भर्ती और पीडीएस जैसे घोटाले हुए हैं, जिसके चलते केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार किया था। चटर्जी और मलिक फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।

सीतारमण ने पूर्व बर्धमान जिले के कालना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हथकरघा और बुनकर प्रकोष्ठ के सूती बुनकर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, यहां तक कि छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत आवंटित राशि का भी लाभार्थियों के फर्जी नामों का इस्तेमाल करके दुरुपयोग किया

पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच में रोहित शर्मा का खेलना संदिग्ध

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। रोहित शर्मा बृहस्पतिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियन्स के इंडियन प्रीमियर लीग मैच से लगभग बाहर हो गए हैं और फिलहाल टीम का मेडिकल स्टाफ उनकी जांच कर रहा है।



पिछले रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु के खिलाफ बड़े स्कोर वाले मैच के दौरान मुंबई इंडियन्स की पारी के छठे ओवर में रोहित को अपने पैर की मांसपेशियों में परेशानी महसूस हुई थी जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे। जब रोहित 'रिटायर्ड हर्ट' होकर बाहर गए तब वह 13 गेंद पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद मुंबई इंडियन्स यह मैच 18 रन

से जुड़ने वाले हैं। वह मौजूदा सत्र में टीम की लगातार तीसरी हार थी। बुधवार को मुंबई इंडियन्स के ट्रेनिंग सत्र के दौरान टीम के एक अधिकारी ने कहा, 'मेडिकल टीम और कोचिंग स्टाफ उनकी जांच कर रहे हैं और हमें जल्द ही पता चल जाएगा।' इस बीच इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स जल्द ही मुंबई इंडियन्स

भाजपा ने पवन खेड़ा पर हमला तेज किया

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर अपना हमला तेज कर दिया, जब शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें एक सप्ताह के लिए दी गई 'ट्रांजिट' अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया कि उन्होंने 'अनावश्यक विवाद' खड़ा किया और अब 'भगोड़े की तरह छिप रहे हैं।' भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि खेड़ा को उच्चतम न्यायालय से 'करारा झटका' लगा है और आरोप लगाया कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी को निशाना बनाकर राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियान चलाया था। पूनावाला ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'सत्य की जीत हुई। पवन खेड़ा ने झूठे दावे किए और असम के बेटे-बेटी के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित अभियान को अंजाम दिया।'

पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी: राज्यपाल आरएन रवि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य की खोई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने के लिए बुधवार को सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने साथ ही लोगों से, खासकर युवाओं से सकारात्मक बदलाव में भागीदारी कर राज्य की ताकत को पुनर्स्थापित करने की अपील की। रवि ने लोक भवन में 'पोड़ला बोइशाख' (बांग्ला नव वर्ष) के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल कभी देश के अग्रणी आर्थिक और बौद्धिक केंद्रों में शुमार था, लेकिन सत्य ही राज्य की मौजूदा आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने



कहा, स्वतंत्रता के समय और उसके बाद के दशकों में बंगाल देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। 1960 के दशक के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 10 प्रतिशत से भी अधिक था। उस दौर में न तमिलनाडु, न

1980 तक केवल चार राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बंगाल से अधिक थी, लेकिन आज ऐसे राज्यों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। राष्ट्रीय आय में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 10.6 प्रतिशत से घटकर करीब पांच प्रतिशत रह गई है। राज्यपाल ने कहा, पोड़ला बोइशाख 2026 संकल्प का दिन है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। निराशा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल को जगाना होगा और अपनी ऊर्जा व विरासत को फिर से हासिल करना होगा। यह मां दुर्गा की भूमि है। हम इसे पुनः गौरव दिलाएंगे। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि राज्य अपनी पुरानी पहचान फिर हासिल करेगा और भारत की वैश्विक विकास यात्रा में अग्रणी भागीदार बनेगा।

सुविचार

बदलाव संसार का नियम है। जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वह पीछे छूट जाता है। नई चीजों को अपनाना सीखें।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

उर्वरक आत्मनिर्भरता का क्रांतिकारी मॉडल

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक एमएल जाट ने उर्वरक आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए जो सुझाव दिए हैं, वे अत्यंत प्रासंगिक हैं। देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। भारत के पास ऐसी कई चीजें हैं, जिन्हें उर्वरकों में बदला जा सकता है। अगर सरकार योजना बनाए, विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दे तो कुछ ही वर्षों में उर्वरक आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। देश में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हमें इतनी बड़ी आबादी को अपनी ताकत बनाना चाहिए। अगर मानव अपशिष्ट से उर्वरक बनाया जाए तो खेती-बाड़ी की जरूरत के बहुत बड़े हिस्से की चरम आपूर्ति हो सकती है। इस काम को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से करना बहुत जरूरी है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई जोखिम न रहे। एक किसान अपना अनुभव कुछ यूँ बताते हैं, 'हमारे गांव के बाहर एक खेत है। पहले, सभी लोग सुबह निवृत्त होने के लिए वहां जाते थे। जब बुआई का समय आता तो लोग वहां जाना बंद कर देते थे। उस खेत में (अन्य खेतों की तुलना में) फसल जोरदार होती थी।' अब घर-घर में शौचालय हैं, जो अच्छी बात हैं। खेतों के आस-पास बसावट भी काफी हो गई है। खुले में शौच जाने के साथ कई जोखिम जुड़े हैं। इससे कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, इसलिए उस अस्वास्थ्यकारी प्रथा की वापसी नहीं होनी चाहिए। आज देशभर में शौचालयों की संख्या करोड़ों में है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जिसके तहत निश्चित अवधियों में शौचालयों से मानव अपशिष्ट लेकर उसे नजदीकी संयंत्र में पहुंचाया जाए और उससे उत्तम उर्वरक बनाया जाए?

मानव मूत्र में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं। ये पौधों की जड़ों के विकास और फूल-फल बनने में मदद करते हैं। साथ ही, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। वैसे तो मानव मूत्र को प्राकृतिक तरल उर्वरक कहा जाता है, लेकिन इसे पौधों में सीधे डालना हानिकारक हो सकता है। इसका उचित विधि से शोधन होना जरूरी है। इसके लिए वैज्ञानिकों की मदद लेनी चाहिए। अगर देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके संयंत्र लगाकर तरल उर्वरक बनाया जाए तो यह आत्मनिर्भरता की ओर बहुत बड़ा कदम होगा। भारत में रोजाना करोड़ों लीटर मानव मूत्र का उत्सर्जन होता है। यह बहुत बड़ा संसाधन साबित हो सकता है। इसमें वेस्ट टू वेल्थ बनने की भरपूर शक्ति एवं सामर्थ्य है। सोफिए, रोजाना कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे लाभदायक तत्वों का नुकसान हो रहा है? अगर चार-पांच दशक पहले संग्रहण एवं शोधन के लिए संयंत्र लगाए जाते तो आज हमारा देश उर्वरकों का कितना बड़ा निर्यातक बन सकता था? इससे देश में स्वच्छता को बढ़ावा मिलता। भारत में आज भी कई जगह जूटा-बासी खाना फेंका जाता है। उसके साथ फलों-सब्जियों के छिलके फेंक दिए जाते हैं। शादी और बड़े आयोजनों के अगले दिन बासी खाने के ढेर लगे रहते हैं। वहां मच्छियां भिन्भिनाती रहती हैं। आवारा पशु भी घमा-बौकड़ी मचाते हैं। कई सब्जी मंडियों में सड़े हुए फल-सब्जीयें ही फेंक दिए जाते हैं। उनकी दुर्गंध से लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसी तरह सूखी पत्तियां या तो जला दी जाती हैं या उनका एक जगह ढेर लगा दिया जाता है, जिसके बाद वे सड़ती रहती हैं। ये सभी चीजें उर्वरक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रकृति द्वारा दी गई कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं होती। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे लाभदायक होते हैं।

ट्वीटर टॉक

राजस्थान का डेयरी सेक्टर आज न सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक मजबूत उदाहरण बन रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, सशक्त नीतियों और हमारे मेहनती पशुपालकों के समर्पण से, हर गाँव में खुशहाली की एक नई कहानी लिखी जा रही है।

-भजनलाल शर्मा

लोकल बॉडी और पंचायत चुनाव न होना कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जैसा है, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट को दखल देना चाहिए। जिस तरह के लीगल वायरलेस व कर रहे हैं, उसे देखते हुए एव सरकार कैसे चल सकती है?

-अशोक गहलोत

एआईसीसी सेक्टर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के को-इन-चार्ज, रुत्विक मकयाना जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए शुभ हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और अपार सफलता लाए।

-सचिन पायलट

प्रेरक प्रसंग

चुगली का पलटवार

चाणक्य के आश्रम में एक शिष्य था, जिसे दूसरों की बातें इधर-उधर पहुंचाकर आनंद मिलता था। उसकी एक आदत ने पूरे आश्रम का माहौल बदल दिया था। वह पहले शांति थी, वहां अब छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने लगे। एक दिन चाणक्य ने उसे पास बुलाया और बिना कुछ कहे एक तकिया धमा दिया। बोले 'जाओ, पूरे गांव में घूमो और इसकी रूई को हवा में उड़ाने जाओ।' शिष्य को यह अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। जब वह लौटकर आया, तो चाणक्य ने शांत स्वर में कहा 'अब जाओ, उन सारे रूई के टुकड़ों को वापस इकट्ठा करके ले आओ।' शिष्य हंस पड़ा 'गुरुजी, यह कैसे संभव है? वे तो हवा में बिखर गए होंगे।' चाणक्य ने कहा 'जैसे ये रूई के टुकड़े हवा में फैलकर कभी वापस नहीं आ सकते, वैसे ही तुम्हारे शब्द भी लोगों के दिलों में फैल जाते हैं। तुम एक पल के आनंद के लिए जो चुगली करते हो, वही आनंद कभी तुम्हारे लिए पलटवार बनकर लौटता है। तब चाहकर भी तुम उसे समेट नहीं पाओगे।' यह सुनते ही शिष्य का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि उसका 'आनंद' वास्तव में दूसरों के दर्द की कीमत पर था।

महत्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor: Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such matter without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law. Regn No. RNI No.: TNHN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबन्धता या धमकावट का व्यवहार करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उपाध्यक्षों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बर्ना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सामयिक

जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के आरोपों से हिला कॉर्पोरेट तंत्र

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

कॉर्पोरेट दफ्तरों की जगमगाहट, कांच की जंजीर इमारतों का मोहक आभास और प्रोफेशनलिज्म के बड़े-बड़े दावे-यदि इनके भीतर भय, शोषण और दबाव का अंधकार पलता हो, तो यह किसी एक कंपनी की चूक नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की गहरी असफलता का संकेत है। अप्रैल 2026 में नासिक स्थित एक आईटी इकाई (टीसीएस) से सामने आया प्रकरण इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जहाँ महिला कर्मियों के सपनों को सुनिश्चित ढंग से रौंद दिया गया। रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा लेकर आई इन महिलाओं को अपने ही कार्यस्थल पर ऐसे असहनीय दबावों का सामना करना पड़ा, जो किसी भी सभ्य समाज के मूल्यों के सर्वथा विपरीत हैं। यह मामला केवल यौन शोषण के आरोपों तक सीमित नहीं है; इसके भीतर भय, मानसिक उत्पीड़न, धार्मिक आस्था पर दबाव और अधिकारों के खुले दुरुपयोग की कहीं अधिक गंभीर परतें छिपी हुई हैं। सामने आई शिकायतों के अनुसार, कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने महिला कर्मियों पर अनुचित प्रस्तावों, अश्लील टिप्पणियों और निजी संबंध बनाने के लिए निरंतर दबाव डाला। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें पदोन्नति रोकने, नौकरी समाप्त करने और उनके निजी जीवन को बर्बाद करने की धमकियाँ दी गईं। सत्ता और पद के बल पर किया गया यह आचरण केवल अनैतिकता की परकाष्ठा नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से कानून दंडनीय अपराध है, जो किसी भी कार्यस्थल की गरिमा, सुरक्षा और विकास को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है।

यह प्रकरण और भयावह तब बनता है, जब स्पष्ट होता है कि यह फिटचुट घटनाएँ नहीं, बल्कि लंबे समय से सक्रिय संगठित तंत्र का परिणाम था। पुलिस जांच और शिकायतों के अनुसार, आठ महिला कर्मचारियों की नौ एफआईआर्स में सामने आया कि टीम लीडर्स सहित वरिष्ठों ने 2022 से 2026 तक करीब चार वर्षों तक सुनिश्चित ढंग से उन्हें निशाना बनाकर दबाव में रखा। पुलिस ने फरवरी से 40 दिन तक महिला पुलिसकर्मियों के जरिए अंडरकवर ऑपरेशन चलाकर साक्ष्य जुटाए। आरोप है कि निजी तस्वीरें-वीडियो से ब्लैकमेल करना, नमाज पढ़ने और गोमांस खाने को मजबूर करना, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव



अब समय केवल औपचारिक प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक सुधार का है। इस प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यापक जांच होनी चाहिए, दोषियों को कठोर दंड मिले और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश) के अनुपालन की स्वतंत्र ऑडिट पूरे आईटी क्षेत्र में कराई जाए।

और मानसिक रूप से तोड़ना-ये सब उसी तंत्र के औजार थे। यह स्थिति दिखाती है कि जब शक्ति का दुरुपयोग संस्थागत रूप ले लेता है, तो पीड़ितों के लिए आवाज उठाना कठिन और जोखिम भरा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पक्ष मानव संसाधन विभाग की भूमिका पर उठते सवाल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश) के तहत हर संगठन में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और समयबद्ध, निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। इसके बावजूद आरोप हैं कि शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, ईमेल और लिखित आवेदन दबाए गए, और पीड़ितों को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया-यहाँ तक कि एक एचआर अतिरिक्त जनरल मैनेजर को भी अनदेखी के आरोप में गिरफ्तार

किया गया। जिस विभाग पर कर्मचारियों की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी होती है, यदि वही निष्क्रिय या सहभागी दिखे, तो यह कानून की अहंहेलना के साथ विश्वास का गंभीर हनन भी है।

चार वर्षों तक लगातार उठती शिकायतों के बावजूद कार्यवाही का अभाव यह स्पष्ट करता है कि समस्या कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की गहरी खामियों में जड़ें जमाए हुए थीं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश) के दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि 24 घंटे के भीतर संज्ञान लिया जाए और 90 दिनों में जांच पूरी हो, परंतु यहाँ इन प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी की गई है। यह मात्र लापरवाही नहीं, बल्कि कानूनी दायित्वों से बचने की प्रवृत्ति का संकेत देता है। ऐसे मामलों में देरी न केवल पीड़ित के मानसिक

आघात को गहरा करती है, बल्कि आरोपियों के हौसले भी बढ़ाती है। जौरो टॉलरेंस की नीति का हवाला तब खोखला लगता है, जब सवाल उठता है कि वर्षों तक शिकायतें दबने और पीड़ितों की आवाज अनसुनी रहने के दौरान यह लागू क्यों नहीं हुई। टीसीएस द्वारा उच्च प्रबंधन स्तर पर जांच (सीओओ के निर्देशन में) के आदेश और आरोपियों का निलंबन आवश्यक कदम हैं, पर पर्याप्त नहीं-क्योंकि नेसेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट ने श्रम मंत्रालय से पोश कम्प्लायंस ऑडिट की मांग की है। जवाबदेही केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; उसे उन सभी स्तरों तक तय होना चाहिए जहाँ लापरवाही या मिलीभगत रही हो। कॉर्पोरेट संस्थानों की साख मुनाफे या छवि से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान, पारदर्शिता और विश्वास से बनती है।

यह घटना किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे आईटी क्षेत्र में कार्यस्थल की सुरक्षा पर गहरे और असहज प्रश्न खड़े करती है। क्या आधुनिक दफ्तर वास्तव में सुरक्षित हैं, या केवल बाहर से सजे-धजे और आकर्षक दिखते हैं? क्या महिलाओं और अन्य कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ेगा? यह प्रकरण स्पष्ट करता है कि जब तक शिकायत तंत्र मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक किसी भी कानून का प्रभाव सीमित और अधूरा रहेगा। कर्मचारियों के भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी आवाज न दबेगी, न अनसुनी होगी-बल्कि उसे गंभीरता से सुना जाएगा और उन्हें समयबद्ध न्याय अवश्य मिलेगा।

अब समय केवल औपचारिक प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक सुधार का है। इस प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यापक जांच होनी चाहिए, दोषियों को कठोर दंड मिले और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश) के अनुपालन की स्वतंत्र ऑडिट पूरे आईटी क्षेत्र में कराई जाए।

साथ ही मानव संसाधन तंत्र को स्पष्ट रूप से जवाबदेह बनाना और कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। कार्यस्थल केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण होना चाहिए। यदि इस घटना से भी ठोस सबक नहीं लिया गया, तो यह महज एक और मामला बनकर रह जाएगा-और यह किसी भी समाज की सबसे बड़ी विफलता होगी।

नजरिया



केंद्र और राज्य के संबंधों के संदर्भ में भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी का नेतृत्व भाजपा के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश इस समन्वय को और मजबूत कर सकता है। यह स्थिति उस दौर की याद दिलाती है जब राज्य और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार होने से नीति निर्माण और क्रियान्वयन में तेजी आई थी। यदि यह तालमेल बना रहता है तो बिहार को इसका लाभ मिल सकता है।

बिहार को मिला नया 'सम्राट'

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना केवल एक व्यक्ति का सपना नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक यात्रा का परिणाम है जो पिछले कई वर्षों से धीरे-धीरे आकार ले रही थी। 243 सदस्यीय विधानसभा में 2025 के चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 202 सीटें मिलीं, जिनमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 89 सीटें थीं, जो उसे सबसे बड़ा दल बनाती हैं। यही संख्या अंततः उस दावे की बुनियाद बनी जिसके सहारे भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय लिया। सम्राट चौधरी का उदय अचानक नहीं हुआ। वे 2024 से उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और वित्त, गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। इससे पहले वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके थे, जो उनके राजनीतिक अनुभव को दर्शाता है। उनका जन्म 1968 में मुंगेर जिले के एक राजनीतिक परिवार में हुआ और उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार सांसद और विधायक रहे। यह पृष्ठभूमि उन्हें सामाजिक आधार और राजनीतिक नेटवर्क दोनों देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे लंबे समय तक भाजपा के मूल कार्यकर्ता नहीं रहे, बल्कि बाद में पार्टी में आए और तेजी से ऊपर उठे, जो यह दर्शाता है कि भाजपा ने उन्हें एक रणनीतिक चेहरा के रूप में विकसित किया।

नीतीश कुमार का राजनीतिक दौर बिहार में लगभग दो दशकों तक प्रभावी रहा। उन्होंने 2005 से लेकर 2026 तक अलग अलग

अवधियों में राज्य का नेतृत्व किया और इस दौरान शासन की एक विशिष्ट शैली विकसित की। उनकी सरकार 20 नवंबर 2025 को बनी और 14 अप्रैल 2026 तक चली। इस लंबे कार्यकाल में उन्होंने प्रशासनिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। अब जब वे पद से हटकर राष्ट्रीय स्तर की भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या उनकी बनाई हुई संरचना को नई सरकार उसी तरह आगे बढ़ा पाएगी।

सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे निरंतरता और बदलाव के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं। उन्होंने स्वयं यह कहा है कि वे राज्य को विकास के नए आयाम पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ यह है कि वे पूरी तरह नई दिशा देने के बजाय पहले से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाएंगे। बिहार जैसे राज्य में जहाँ प्रशासनिक ढांचा धीरे धीरे स्थिर हुआ है, वहाँ अचानक बड़े बदलाव जोखिम भरे हो सकते हैं। इसलिए संभावना यही है कि नीति के स्तर पर निरंतरता बनी रहेगी, जबकि कार्यशैली में परिवर्तन दिखाई देगा।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू जातीय और सामाजिक समीकरण भी है। बिहार की राजनीति में पिछले वर्षों की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। सम्राट चौधरी कुशाहा समुदाय से आते हैं, जो राज्य की बड़ी आबादी में शामिल है और जिसे राजनीतिक रूप से संगठित करने की कोशिश लंबे समय से होती रही है। भाजपा ने उन्हें आगे करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि वह केवल पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सामाजिक आधार का विस्तार करना चाहती है। यह कदम उस रणनीति का परिणाम है, जिसके तहत पार्टी क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत कर राष्ट्रीय

राजनीति में भी संतुलन बनाना चाहती है।

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच संबंध भी इस परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण हैं। दोनों ने लंबे समय तक एक साथ काम किया और सम्राट चौधरी को दो बार उपमुख्यमंत्री बनाया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि नेतृत्व परिवर्तन पूरी तरह टकराव का परिणाम नहीं है, बल्कि एक नियोजित प्रक्रिया का हिस्सा है। यह भी माना जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, जिससे सत्ता का संक्रमण सहज हो सके। यही कारण है कि इस बदलाव को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के नजरिये से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे साझेदारी के नए चरण के रूप में समझना चाहिए।

इस परिवर्तन के साथ बिहार की राजनीति में तुलना का आधार भी बदल जाएगा। अब तक राज्य में विकास और शासन की चर्चा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के संदर्भ में होती थी। लेकिन अब यह तुलना सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच होगी। यह बदलाव केवल व्यक्तिगत का नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी है। अब यह देखा जाएगा कि क्या नई सरकार उसी गति से विकास कर पाती है या उससे आगे निकलती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष है कि आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष और तीखा होगा। विपक्ष यह दिखाने की कोशिश करेगा कि यह बदलाव जनता की इच्छा के बजाय राजनीतिक समीकरणों का परिणाम है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन इसे विकास और स्थिरता के

लिए जरूरी कदम के रूप में प्रस्तुत करेगा।

केंद्र और राज्य के संबंधों के संदर्भ में भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी का नेतृत्व भाजपा के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश इस समन्वय को और मजबूत कर सकता है। यह स्थिति उस दौर की याद दिलाती है जब राज्य और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार होने से नीति निर्माण और क्रियान्वयन में तेजी आई थी। यदि यह तालमेल बना रहता है तो बिहार को इसका लाभ मिल सकता है।

हालांकि चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अभी भी सुधार की बड़ी जरूरत है। सम्राट चौधरी के सामने यह अवसर भी है और परीक्षा भी कि वे इन क्षेत्रों में ठोस परिणाम दिखा सकें। यदि वे केवल राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में ही उलझे रहते हैं तो उनकी सरकार पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं। दूसरी ओर यदि वे प्रशासनिक दक्षता और विकास के नए मानक स्थापित करते हैं तो वे अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं।

समग्र रूप से देखा जाए तो बिहार में यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक संरचना के पुनर्गठन का संकेत है। इसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व मौजूद हैं। एक ओर नीतीश कुमार की विरासत है, दूसरी ओर भाजपा की नई रणनीति और सम्राट चौधरी का नेतृत्व। आने वाला समय यह तय करेगा कि यह प्रयोग कितना सफल होता है और क्या यह बिहार की राजनीति को नई दिशा दे पाता है। फिलहाल इतना निश्चित है कि राज्य एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है जहाँ पुरानी विरासत और नई आकांक्षाएँ एक साथ चलेंगी।



अनुभूति के 'गुलिस्तां' में सजी गज़लों की एक शाम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय 'अनुभूति' साहित्यिक संस्था द्वारा रविवार को कोला सरस्वती विद्यालय सभागार में सांस्कृतिक संध्या 'गुलिस्तां' का आयोजन किया जिसमें गजल,

गीत शयरी की प्रस्तुति हुई। अध्यक्ष विजय गोयल ने सभी का स्वागत किया। महासचिव नीलम सारडा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन गोविंद मूंदड़ा ने किया। अनुभूति के सदस्यों महेश नक्श, मोहिनी चोरडिया, शकुंतला करनानी, मिडू मिठास, उषा टिबरेवाल,

आलोक जायसवाल, शिल्पा जैन द्वारा गजलें प्रस्तुत की गईं। श्रेणिक नाहर के नेतृत्व में सेजल पारख, मनीषा शाह, भय्याता गोलेछा, वैभव समदडिया, धृति बैद एवं हेनल शाह आदि कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति दी। सचिव शिल्पा जैन न धन्यवाद दिया।



कावेरी हार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा विशेष कार्डियक कार्यक्रम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के कावेरी अस्पताल के कावेरी हार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा कॉम्प्लेक्स हाई-रिस्क इंडिकेटेड प्रोसीजरर्स (सीएचआईपी) नामक विशेष कार्डियक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य सबसे जटिल और उच्च जोखिम वाली हृदय स्थितियों का प्रबंधन करना है। इस पहल का उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार रोगियों का इलाज करना है जिनमें गंभीर दिल का दौरा, उन्नत हृदय विकलता और कार्डियोजेनिक शॉक से पीड़ित रोगी शामिल हैं, जिनके लिए अत्याधुनिक तकनीक, बहु-विषयक विशेषज्ञता और समय पर आपातकालीन देखभाल को मिलाकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। सीएचआईपी के लिए उत्कृष्टता केंद्र में एक उच्च समन्वित बहुविषयक टीम है जिसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट,

कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेसिस्ट और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ शामिल हैं जो त्वरित निर्णय लेने और उपचार सुनिश्चित करने के लिए संरचित प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए एक साथ काम करते हैं। इस पहल का शुभारंभ करते हुए कावेरी अस्पताल के मुख्य हृदयरोग विशेषज्ञ प्रो. अजीत पिलई ने कहा कि कई मरीज गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचते हैं, कभी-कभी तो उनकी जान बाल-बाल बचती है। ऐसा किसी अचानक हुई घटना के कारण होता है, जैसे कि दिल का दौरा पडना जब कोई गंभीर रूप से बीमार मरीज अस्पताल पहुंचता है, तो अस्पताल के डॉक्टरों की टीम 10-15 मिनट के भीतर उसकी स्थिति का आकलन करके इलाज शुरू कर देती है, जिससे समय रहते जीवन रक्षक उपाय किए जा सकते हैं। कई मामलों में, जटिल हृदय प्रक्रियाओं के दौरान हृदय को अस्थायी रूप से सहारा देने के लिए ईसीएमओ और माइक्रो-एक्सिल

कार्डियक पंप जैसे उन्नत यांत्रिक परिसंचरण सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और यूरोप के प्रमुख हृदय अस्पतालों में प्रचलित मॉडल के समान टीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं। कावेरी गुप ऑफ हॉस्पिटल्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. अरविंदन सेल्वरज ने कहा कि अत्यंत गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के इलाज में समय पर हस्तक्षेप, नैदानिक विशेषज्ञता और विभिन्न विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है। सीएचआईपी को अपनाया हृदय संबंधी देखभाल के वैश्विक मानकों को मरीजों के करीब लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्नत प्रौद्योगिकी, बहु-विषयक विशेषज्ञता और मजबूत देखभाल प्रणालियों को एकिकृत करके, हमारा लक्ष्य विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले और आपातकालीन मामलों के परिणामों में सुधार करना है।

सद्गुरु आत्मा को भवोभव संवारते हैं : आचार्य कुलबोधिसूरीशवर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। आचार्यश्री कुलबोधिसूरीशवरजी के सांख्यिक बुधवार को गुजराती जैनवाड़ी में आचार्य भुवनभानुसूरीशवरजी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित गुरु गुणोत्सव श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं से ओत-प्रोत वातावरण में संपन्न हुआ। आचार्यश्री ने कहा कि गुणानुवाद सभा उन महापुरुषों के लिए होती है, जिन्होंने अपने आत्मगुणों को जागृत कर समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है।

उन्होंने कहा कि सद्गुरु का उपकार माता-पिता से भी बढ़कर होता है, क्योंकि वे आत्मा का कल्याण कर भवोभव संवार देते हैं।



अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जीवन के तीन महत्वपूर्ण आधारों, मां, महात्मा और परमात्मा का उल्लेख किया और बताया कि तीनों में मा अक्षर की समानता है। मां बचपन को संवारती है, महात्मा जीवन को दिशा देते हैं और

■ गुणानुवाद सभा में गूंजे आचार्य भुवनभानुसूरी के महिमा गान

उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में संयम, मधुरता, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम था। उनका संयम जीवन उच्च कोटि का था और उनकी मधुर वाणी तथा तत्त्वचिंतन ने उन्हें विशिष्ट स्थान दिलाया। वे परमात्मा भक्ति में सदैव लीन रहते थे तथा उनके लेखन में वैराग्य की गहराई स्पष्ट झलकती थी।

उन्होंने कहा कि जिनशासन की 2600 वर्षों की गौरवशाली परंपरा अनेक श्रमण-श्रमणियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। आचार्य भुवनभानुसूरीशवरजी ने अनेक गुणों का अद्भुत समावेश था। वे विश्वास के सागर, प्रतिभा के धनी और विचारों के विराट भंडार थे। गुरु के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण अद्वितीय था। इस अवसर पर पंच्यास ज्ञानबोधि विजयजी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सद्गुरु भक्तकी आत्माओं को सही मार्ग पर लाने का कार्य करते हैं। आचार्य भुवनभानुसूरीशवरजी ज्ञान और क्रिया के अद्भुत समन्वय के प्रतीक थे। वे स्वयं के प्रति कठोर और शिष्यों के प्रति अत्यंत कोमल थे। उनके जीवन में जागृति, निर्मल चरित्र, सुलझा हुआ व्यवहार और गुरु भक्ति जैसे उत्कृष्ट गुण समाहित थे।

श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को प्राथमिक डीलर कारोबार की मंजूरी मिली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। श्रीराम फाइनेंस ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि उसकी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली अनुष्णगी कंपनी, श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को आज यानी 15 अप्रैल, 2026 को शर्तों के पालन के अधीन, रिजर्व बैंक प्राथमिक डीलर (पीडी) कारोबार शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

मन को शांति के लिए सकारात्मक उर्जा आवश्यक : ब्रह्मर्षि भानुप्रताप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के गांधीनगर स्थित वैष्णव भवन में ग्वालियर के बालाजी मठ मंदिर धार्मिक एवं पुण्यार्थ लोक न्यास के अध्यक्ष ब्रह्मर्षि भानुप्रताप दुवे ने अपने प्रवचन में कहा कि हृदय में सत्य को स्थापित करने के बाद ही मन, बुद्धि, चित्त में सच्चिदानंद परमात्मा के प्रति अनुराग होता है वही अनुराग जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। मन को शांति और सुख के अनुभव के लिए सकारात्मक उर्जा की आवश्यकता होती है जो परमेश्वर कृपा से अंतरिक्ष से मिलती है और नकारात्मक उर्जा अशुभ ग्रह एवं पितृ दोष के कारण मिलती है। अशुभ प्रभाव से बचने व शुभ प्रभाव



के आगमन के लिए ही सत्संग और दान की महत्त्वता है जिसे हर व्यक्ति को प्राथमिकता से अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचतत्व से बने मानव शरीर की रचना, चेतना यानी परमसत्ता परमेश्वर के अनुभव के लिए प्रदत्त है जिसको समझना ही बुद्धिमता है।

कल विल्सनगार्डन में होगा समकितमुनि का बेंगलूरु नगर प्रवेश

बेंगलूरु। चेन्नई से चातुर्मास सम्पन्न कर विभिन्न शहरों में विचरण करते हुए बेंगलूरु में चातुर्मास करने आ रहे डॉ. समकितमुनिजी, भवांतमुनिजी एवं जयवंतमुनिजी का बेंगलूरु नगर प्रवेश शुक्रवार को धैतावर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ विल्सनगार्डन में होगा। संघ के चेयरमैन मीठालाल मकाणा, अध्यक्ष नेमीचंद भंसाली, मंत्री सज्जन बोहरा ने बताया कि संतश्री आडुगोडी स्थित तेरापंध

सभा भवन से शुक्रवार को प्रातः 7: 35 बजे विहार करके शोभायात्रा के साथ चित्रयनपाल्या विल्सन गार्डन स्थित जैन स्थानक में पधारेंगे। नगर प्रवेश कार्यक्रम हेतु संघ में विशेष उत्साह छाया हुआ है। ज्ञातव्य है कि डॉ. समकितमुनि आदि का इस वर्ष का चातुर्मास बेंगलूरु चातुर्मास समिति-2026 के तत्वावधान में महावीर धर्मशाला में तय है।

एवरविन गुप्स ऑफ स्कूल्स के दसवीं का रिजल्ट रहा शत प्रतिशत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। कोलाथुर स्थित एवरविन गुप्स ऑफ स्कूल्स के विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी दसवीं के परीक्षा परिणामों में शत प्रतिशत सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।



छात्र एम कौशिक ने कुल 500 में से 493 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मधुकर जैन अस्पताल में ब्लडसुगर की जांच की मशीन स्थापित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां पेरम्बूर के युवाचार्य मधुकर मुनि जैन हॉस्पिटल के प्रांगण में भगवान महावीर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में हॉस्पिटल में ब्लडसुगर मशीन का उद्घाटन मुख्य अतिथि शांतिलाल विनोदकुमार सिंघवी ने किया। यह मशीन इन्हीं के द्वारा दी गयी है। ये मशीन मरीजों के पिछले तीन महीनों का औसत ब्लड शुगर स्तर कुछ मिनटों में बतायेगी। इससे

डायबिटीस की सटीक जांच और बेहतर इलाज में मदद मिलेगी। इससे मरीजों को लम्बे इन्तजार में राहत मिलेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष पारसमल सुराणा ने कहा कि हमारा उद्देश्य मरीजों को त्वरित और विश्वसनीय सेवाएं देना है। मंत्री चेतन पटवा ने हॉस्पिटल में नवयुवकों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का आह्वान किया है। जिससे संस्था आने वाले दिनों में प्रगति करती रहे। नवयुवक पंकज पटवा, कुणाल तातेड़, पूतम खिचसरा, तेजस सकलेचा, आनन्द विनायकिया, आकाश

मेहता, यश बोहरा, अभिषेक डामा, विनय छल्लाणी, रूपेश सुराणा, राजेश पोकरण ने समाह में एक दिन अस्पताल में आकर अपनी निःस्वार्थ सेवाएं देने की बात कही। इस मौके पर हॉस्पिटल के उपाध्यक्ष विजय तातेड़, सह मंत्री गौतम सकलेचा, सहकोषाध्यक्ष संजय मेहता, रिखबचंद लोड़ा, रुपराज कोठारी, अजीत पटवा, भंवरलाल खिचसरा, महेंद्र तातेड़, इन्दरचन्द विनायकिया, करण छल्लाणी, राजेश समदडिया, सुरेश समदडिया, अशोक लोड़ा, उगम बोहरा आदि उपस्थित थे।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

चुनाव प्रचार



कोयंबटूर उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्षेत्र की उम्मीदवार वनाथी श्रीनिवासरन के समर्थन में एक रोड़ शो किया। वनाथी श्रीनिवासरन इस समय एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रही हैं। रेखा गुप्ता ने अविना पत्नी, (भकूल), वेंकटपुरम, के.के. पुदुर, चित्रमल नगर, एस्वीआई रोड़, कन्नप्पन नगर, और नारायणसामी लेआउट का दौरा किया। उन्होंने सभी से वनाथी के लिए मतदायचना की।